

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 08 नवंबर, 2023

इस मामले में:

ले.पे.अ. 118/2023 और सि.वि. संख्या 7868/2023, सि.वि. संख्या 7871/2023

भारत संघ और अन्य

..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री किर्तीमान सिंह, सीजीएससी के साथ सुश्री मनमीत कौर सरिन, सुश्री विधि जैन, अधिवक्तागण

बनाम

भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड

..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री रोहन शाह, श्री आलोक यादव और सुश्री श्रीसबरी राजन, अधिवक्तागण।

ले.पे.अ. 229/2023 और सि.वि. संख्या 16268/2023, सि.वि. संख्या 16271/2023

भारत संघ और अन्य

..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री किर्तीमान सिंह, सीजीएससी के साथ सुश्री मनमीत कौर सरिन, सुश्री विधि जैन, अधिवक्तागण

बनाम

सिप्ला लिमिटेड

..... प्रत्यर्थी

द्वारा: सुश्री अर्चना सहदेव, अधिवक्ता।

ले.पे.अ. 119/2023 और सि.वि. संख्या 7877/2023, सि.वि. संख्या. 7880/2023

भारत संघ और अन्य

..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री किर्तीमान सिंह, सीजीएससी
के साथ सुश्री मनमीत कौर सरिन,
सुश्री विधि जैन, अधिवक्तागण

बनाम

भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड

..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री रोहन शाह, श्री आलोक यादव
और सुश्री श्रीसबरी राजन,
अधिवक्तागण।

ले.पे.अ. 142/2023 और केवियट सं. 115/2023, सि.वि. सं. 9265/2023,
सि.वि. सं. 9268/2023

भारत संघ और अन्य

..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री किर्तीमान सिंह, सीजीएससी
के साथ सुश्री मनमीत कौर सरिन,
सुश्री विधि जैन, अधिवक्तागण

बनाम

बार्ड हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

..... प्रत्यर्थी

द्वारा: सुश्री कृष्ण सरमा, श्री कुमार और
सुश्री अर्चिता फुकुन,
अधिवक्तागण।

ले.पे.अ. 227/2023 और सि.वि. संख्या 16242/2023, सि.वि. संख्या
16245/2023

भारत संघ और अन्य

..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री किर्तीमान सिंह, सीजीएससी
के साथ सुश्री मनमीत कौर सरिन,
सुश्री विधि जैन, अधिवक्तागण

बनाम

पॉली मेडिक्योर लिमिटेड

..... प्रत्यर्थी

कोरम:

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुब्रमण्यम प्रसाद

निर्णय

1. लेटर्स पेटेंट अपीलस (एल. पी. ए.) का तत्काल बैच एल. पी. ए. संख्या: 118/2023; 119/2023; 142/2023; 227/2023; और 229/2023 को रिट.या. (सि) सं 7946/2018; 8190/2018; 9090/2020; 2521/2021; और 3358/2020 (अंतर्निहित रिट याचिकाएं) दिनांकित 22.09.2022 (रिट.या. (सि) सं 7946/2018; 8190/2018 और 9090/2020 में सामान्य निर्णय दिया); दिनांकित 04.11.2022 (रिट.या. (सि) सं 2521/2021 में निर्णय); और दिनांकित 06.10.2022 (रिट.या. (सि) सं 3358/2020 में निर्णय) में क्रमवार पारित आक्षेपित निर्णयों में दायर किया गया हैं। अंतर्निहित रिट याचिकाएँ यहाँ प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर की गई है, जो फार्मास्युटिकल कंपनियाँ हैं, राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ("एनपीपीए") द्वारा उन्हें जारी किए गए मांग नोटिस पर हमला करते हुए जिसमें अभिनिर्धारित किया गया कि प्रत्यर्थीगण ने औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 ("2013 डीपीसीओ") के पैराग्राफ 20 ("पैरा 20") के उल्लंघन में उनके द्वारा निर्मित कुछ औषधि विनिर्मिति के लिए उपभोक्ताओं से अतिप्रभार लेने का दोषी ठहराया गया है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने सभी अंतर्निहित रिट याचिकाओं को स्वीकार कर

लिया है, और इसमें अपीलार्थियों ने तत्काल एलपीए के माध्यम से इसे चुनौती देने को प्राथमिकता दी है, जिसमें कहा गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 की व्याख्या करने में गलती की है और इसके वास्तविक सार को खोजने में विफल रहे हैं।

2. इस बिंदु पर, 2013 डीपीसीओ. के पैरा 20 को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा जो निम्नानुसार है:

“20. गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों के कीमतों की निगरानी करना।-

(1) सरकार गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों सहित सभी औषधियों के अधिकतम खुदरा मूल्यों (एमआरपी) की निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी निर्माता पिछले बारह महीनों के दौरान किसी औषधि के अधिकतम खुदरा मूल्य में अधिकतम खुदरा मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक की वृद्धि न करे और जहां वृद्धि अधिकतम खुदरा मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक है, वह अगले बारह महीनों के लिए इसे अधिकतम खुदरा मूल्य के दस प्रतिशत के स्तर तक कम कर देगी।

(2) विनिर्माता जुर्माने के अतिरिक्त कीमत में वृद्धि की तारीख से ब्याज के साथ अतिप्रभारित राशि जमा करने के लिए उत्तरदायी होगा।”

3. 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 के अवलोकन से पता चलता है कि इसे दो अलग-अलग और पहचान योग्य भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में प्रावधान है कि गैर-अनुसूचित विनिर्मिति का निर्माता पिछले बारह महीनों के दौरान ऐसे गैर-अनुसूचित विनिर्मिति के अधिकतम खुदरा मूल्य (“एमआरपी”) में

एमआरपी के 10 प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है और अगले बारह महीनों के लिए उक्त एमआरपी को संरक्षित कर सकता है। यह सरकार पर इस तरह के गैर-अनुसूचित विनिर्मिति के एमआरपी में वृद्धि की निगरानी करने का दायित्व भी डालता है ताकि अगले वर्ष या उसी वर्ष एमआरपी में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि न हो। 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 का दूसरा भाग एक निर्माता द्वारा किए गए उल्लंघन के परिणामों से संबंधित है, यदि यह पिछले बारह महीनों के दौरान गैर-अनुसूचित विनिर्मिति की एमआरपी को एमआरपी के 10% से अधिक बढ़ा देता है।

4. तत्काल अपीलों में अपीलार्थियों ने स्वयं को 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 की व्याख्या से संबंधित मुद्दे तक ही सीमित रखा है और इसलिए यह न्यायालय प्रत्येक मामले के तथ्यों पर गौर नहीं कर रहा है और खुद को 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 की व्याख्या से संबंधित प्रश्न तक ही सीमित कर रहा है। यह कहना पर्याप्त है कि यहां प्रत्यर्थीगण (विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष याचिकाकर्ताओं) ने 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 के उल्लंघन के लिए अपीलार्थियों द्वारा उन्हें जारी किए गए विभिन्न मांग नोटिसों को चुनौती देने वाली अंतर्निहित रिट याचिकाओं के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

5. विद्वान एकल न्यायाधीश ने पक्षों को विस्तार से सुनने और अभिलेख का अवलोकन करने के बाद, रि.या.(सि.) 7496/2018, रि.या.(सि.) संख्या 8190/2018 और रि.या.(सि.) संख्या 9090/2020 में दिनांक 22.09.2022 को

एक विस्तृत निर्णय पारित किया। जिसका पालन रि.या.(सि.) संख्या 3358/2020 में पारित निर्णय दिनांक 06.10.2022 और रि.या.(सि.) संख्या 2521/2021 में पारित निर्णय दिनांक 04.11.2022 में किया विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने दिनांक 22.09.2022 के फैसले में जो निष्कर्ष निकाले, उन्हें निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

97. इस बैच में उठाए गए मुद्दों पर गौर करने के बाद, न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज करने आता है

क. 2013 डीपीसीओ गैर-अनुसूचित विनिर्मिति की कीमत को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित करने के लिए संघ द्वारा लिए गए सचेत निर्णय का प्रतिनिधित्व करता है, बशर्ते कि वार्षिक वृद्धि 10% से अधिक न हो और अधिक कीमत वसूलने की स्थिति में निर्माता को कीमतों को कानूनी रूप से स्वीकार्य पिछली कीमत पर वापस लाना होगा और अगले बारह महीनों के लिए इसे उसी स्तर पर बनाए रखना होगा।

ख. उस पृष्ठभूमि में देखने पर यह स्पष्ट होता है एक गैर-अनुसूचित विनिर्मिति का निर्माता अपनी औषधि की कीमत तय

करने का हकदार था, बशर्ते कि वह 10% की शर्त का अनुपालन करता हो, जिसे मंजूरी दे दी गई थी।

ग. निर्विवाद रूप से, गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों 2013 डीपीसीओ के तहत मूल्य नियंत्रण की दृढ़ता के अधीन नहीं हैं। यह प्रावधान बस सरकार पर यह निगरानी रखने का दायित्व डालता है कि ऐसे विनिर्मित की अधिकतम खुदरा कीमत पिछले बारह महीनों में प्रचलित कीमत के 10% से अधिक न हो। इस प्रिस्क्रिप्शन में निहित हितकर उद्देश्य इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि औषधि की कीमतों को सरकार द्वारा आवश्यक रूप से विनियमित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मरीजों और उपभोक्ताओं को कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी का सामना न करना पड़े और मुनाफाखोरी को नियंत्रित किया जा सके।

घ. हालाँकि, पैरा 20 निस्संदेह निर्माता को अधिकतम खुदरा मूल्य में वार्षिक वृद्धि करने की अनुमति देता है, बशर्ते कि मूल्य वृद्धि मूल्य के 10% से अधिक न हो जो पिछले बारह महीनों में प्रचलित था। उपरोक्त प्रिस्क्रिप्शन के उल्लंघन के परिणामों को भी अटकलों के लिए खुला नहीं छोड़ा गया है, जिसमें पैरा 20 में स्पष्ट और सुस्पष्ट शब्दों में दंड के साथ-साथ

उपचारात्मक उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें अपनाया जाना चाहिए।

ड. महत्वपूर्ण रूप से, पैरा 20 अतिप्रभार के मामले में किसी औषधि के खुदरा मूल्य को सालाना बढ़ाने के अधिकार से वंचित करने की परिकल्पना नहीं करता है। पैरा 20 में इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने की स्थिति में विनिर्माता को दंडित करने के साथ-साथ परिणामों के बारे में भी बताया गया है और दंड भी निर्धारित किया गया है। प्रत्यर्थागण द्वारा इस आशय का रुख अपनाया गया कि इस तरह की वृद्धि की मांग करने का अधिकार तब तक खोया रहेगा जब तक कि कीमत को संशोधित और कम नहीं किया जाता है, यह न केवल पैरा 20 को खारिज करने के समान होगा, बल्कि अधिक मौलिक शर्तों पर, एलपीए 118/2023 आदि की शुरुआत के परिणामस्वरूप दंडात्मक परिणाम भी होगा। जो न तो उस प्रावधान को स्पष्ट रूप से पढ़ने से उत्पन्न होता है और न ही अनुमान लगाया जा सकता है।

च. पैरा 20 के आशय पर प्रकाश डालने वाली महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियाँ "पूर्वगामी" और "अगली" अभिव्यक्तियाँ हैं। शब्द "पूर्ववर्ती" उस तिथि या अवधि के सूचक के रूप में कार्य करता है

जो कानूनी रूप से स्वीकार्य एमआरपी की पहचान करने के लिए मुख्य बिंदु का गठन करेगा जिसके संदर्भ में उल्लंघन की जांच की जा सकती है। शब्द "अगला" उस अवधि को दर्शाता है और निर्धारित करता है जिसके दौरान विनिर्मिति की एमआरपी को वापस लाने के बाद स्थिर रखा जा सके। वैध एमआरपी की पहचान करने के प्रयोजनों के लिए, जिसके विरुद्ध आवधिक 10% वृद्धि का दावा किया जा सकता है, यह पिछले वर्ष में प्रचलित कीमत है जो नियंत्रित और निर्णय लेगी।

छ. इसी प्रकार, जिस अवधि के दौरान एमआरपी को संशोधित किया जाना चाहिए और होल्ड पर रखा जाना चाहिए, वह भी उल्लंघन की तारीख या अवधि के संदर्भ में गणना करने पर अगले बारह महीने के लिए निर्धारित किया गया है। उस अवधि की शुरुआत और साथ ही समाप्ति, जिसके दौरान एमआरपी स्थिर रहना चाहिए, की गणना आवश्यक रूप से उस तारीख या अवधि के संदर्भ में की जानी चाहिए, जिसके दौरान निर्माता ने अतिप्रभार लिया है।

ज. जबकि न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि यहां शामिल मुद्दे औषधियों से संबंधित हैं और उक्त आवश्यक वस्तु को उचित और न्यायसंगत तरीके से बेचने और वितरित करने पर सर्वोपरि विचार है, लेकिन वह खुद को पैरा 20 में दंडात्मक

परिणाम पेश करने या पढ़ने में असमर्थ पाता है। जिसे अन्यथा क़ानून के लेखकों द्वारा शामिल नहीं किया गया है। यह इस न्यायालय का कार्य नहीं है कि वह धार्मिकता की अपनी समझ या धारणा पर कोई दंडात्मक परिणाम बनाए या लागू करे।

झ. इसलिए पैरा 20 को गैर-अनुसूचित विनिर्मिति के निर्माताओं को अपने उत्पादों की कीमत तय करने का अधिकार प्रदान करने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, बशर्ते कि वृद्धि 10% की शर्त का अनुपालन करती हो। पैरा 20 के बाद वाले हिस्से का उल्लंघन करने और अधिक शुल्क वसूलने के बावजूद निर्माता का वह अधिकार इसमें शामिल होने का हकदार होगा।

ज. 10% की वृद्धि केवल पैरा 20 के उल्लंघन के बाद बारह महीने की अवधि के लिए समाप्त हो जाएगी, जहां किसी निर्माता ने उस प्रावधान का अतिप्रभार लिया हो और उल्लंघन किया हो।

ट. पैरा 20 के उल्लंघन और अतिप्रभारित की घटना घटित होने की स्थिति में, निर्माता औषधि की कीमत को उस स्तर पर वापस लाने के लिए उत्तरदायी होगा जिस पर वह उल्लंघन

से पहले थी और उस कीमत को तारीख या अतिप्रभारित की अवधि के बाद बारह महीने तक रोक कर रखेगा।

ठ. अतिप्रभारित के मामले में उत्पन्न होने वाली देनदारी की गणना के प्रयोजनों के लिए, एनपीपीए उस तारीख या अवधि की पहचान करने के लिए बाध्य होगा जिसके दौरान औषधि की कीमत पैरा 20 का उल्लंघन करती है और निर्माता को बारह महीने की अवधि के लिए उस घटना से पहले प्रचलित कीमत पर वापस लौटने की आवश्यकता होगी।

ड. हालाँकि, औषधि की कीमत वापस लेने और उसे उस स्तर पर स्थिर रखने का दायित्व पैरा 20 के तहत निर्धारित बारह महीने की अवधि से अधिक नहीं हो सकता है और मांग बढ़ने तक या उल्लंघन ठीक होने तक जारी रह सकता है। किसी भी मामले में निर्माता को उल्लंघन की तारीख या अवधि के बीच की अवधि के लिए मांग बढ़ने की तारीख तक या निर्माता द्वारा स्वयं उल्लंघन को ठीक करने तक कीमत स्थिर रखने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

द. अतिप्रभारित से संबंधित देनदारी की गणना करते समय, एनपीपीए को कानूनी रूप से स्वीकार्य कीमत को ध्यान में रखना होगा जिसे उल्लंघन की तारीख या अवधि से शुरू होने वाले अगले बारह महीनों में लागू किया जाना चाहिए, भले ही इसके लिए कोई संवैधानिक संगणनात्मक अभ्यास किया जा रहा हो।

ण. ऐसे मामले में जहां उल्लंघन का पता कई वर्षों बाद चलता है, वास्तविक देनदारी पर पहुंचने के लिए, कानूनी रूप से स्वीकार्य एमआरपी का पता लगाने के लिए प्राधिकरण को घड़ी को पीछे करना होगा और पीछे की ओर गणना करनी होगी जिसे लागू किया जाना है और बारह महीने की अवधि जिसके दौरान उस कीमत को संरक्षित किया जाना चाहिए।

त. हालाँकि, "अगले बारह महीनों" के बाद की क्रमिक अवधि के लिए, निर्माता 10% वृद्धि का दावा करने का हकदार होगा जो अन्यथा पैरा 20 के पहले भाग के आधार पर स्वीकृत है। देनदारी की गणना के लिए अंतिम अतिप्रभारित राशि की अनुमानित गणना करते समय इसे आवश्यक रूप से ध्यान में रखना होगा।

थ. पैरा 20 को ऐसे तरीके से लिखा गया है जो पैरा 13 से बिल्कुल अलग है। पैरा 20(1) स्पष्ट रूप से एक स्व-नियामक तंत्र स्थापित करता प्रतीत होता है जो विनिर्माता को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है कि गैर-अनुसूचित विनिर्मिति के लिए वह जो कीमत तय करता है वह पिछले बारह महीनों में प्रचलित कीमत के 10% से अधिक न हो। उपरोक्त प्रावधान के उल्लंघन के मामले में निर्माता पर जो जुर्माना लगाया जाएगा, वह उस प्रावधान में ही स्पष्ट रूप से और सुस्पष्ट रूप से वर्णित है, जब यह निर्धारित होता है कि यदि कोई निर्माता 10% की अधिकतम अनुमेय वृद्धि का उल्लंघन करता है, तो वह अतिप्रभारित राशि को ब्याज सहित जमा करने के लिए बाध्य होगा।

द. महत्वपूर्ण रूप से, उपरोक्त प्रिस्क्रिप्शन का अनुपालन एनपीपीए द्वारा दिए जाने वाले आदेश पर निर्भर या उसके अधीन नहीं है। पैरा 20 को 1995 डीपीसीओ के पैरा 13 से अलग स्थिति में रखने वाली बात यह है कि बाद वाले के विपरीत, जिसमें उस तारीख से ब्याज लगाने की परिकल्पना की गई है जब कोई निर्माता मांग का अनुपालन करने में विफल रहता है, पूर्व किसी भी तरह की मांग पर आधारित नहीं है। पैरा

20 के तहत, अतिप्रभारित की घटना होने पर निर्माता क्षतिपूर्ति के लिए कदम उठाने के लिए उत्तरदायी हो जाता है। इस प्रकार पैरा 20 के तहत उत्प्रेरक घटना स्वयं अतिप्रभारित का कार्य है।

ध. उप पैरा (2) स्पष्ट और सुस्पष्ट शब्दों में आदेश देता है कि कीमत में वृद्धि की तारीख से अतिप्रभारित राशि पर ब्याज देय होगा। अभिव्यक्ति - कीमत में वृद्धि की तारीख को आवश्यक रूप से उस तारीख या अवधि का एक स्पष्ट संदर्भ समझा जाना चाहिए, जिस पर ब्याज विश्वसनीय माना जाता है। पैरा 20(2) इस प्रकार संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता प्रतीत होता है कि ब्याज का भुगतान ऐसी कीमत में वृद्धि की तारीख से किया जाना चाहिए।

न. पैरा 20 न तो नोटिस जारी करने पर विचार करता है और न ही यह "उपार्जित" राशि के सिद्धांत को अपनाता है जैसा कि 1995 डीपीसीओ के तहत परिकल्पित किया गया था। टी.सी. हेल्थकेयर और उसके बाद आने वाले सभी निर्णय अनिवार्य रूप से 1995 डीपीसीओ के पैरा 13 के प्रावधानों का अर्थ लगा रहे थे। हालाँकि, पैरा 20 के संदर्भ में उत्प्रेरक बिंदु कोई नोटिस या मांग नहीं है बल्कि अतिप्रभारित की घटना है। दूसरे, उप पैरा (2)

स्पष्ट शब्दों में निर्धारित करता है कि ब्याज मूल्य में वृद्धि की तारीख से विश्वसनीय होगा। इस प्रकार, पैरा 20(2) की भाषा ब्याज के साथ अधिक वसूली गई राशि को जमा करने के दायित्व के अग्रदूत के रूप में मांग के नोटिस की अवधारणा को पेश करने के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ती है।

प. ब्याज सहित देय राशि का भुगतान करने का दायित्व किसी भी राशि से संबंधित है जो अधिनियम की धारा 3 के तहत किए गए किसी भी आदेश के अनुसरण में वसूली योग्य हो सकती है। 2013 डीपीसीओ, और जिसका पैरा 20 एक अभिन्न अंग है, स्वयं उस अधिनियम की धारा 3 के तहत दिया गया एक आदेश है। इस प्रकार, कीमत में वृद्धि की तारीख से ब्याज का भुगतान करने का दायित्व, जो कि पैरा 20 के आलोक में बनाया गया है, धारा 3 के तहत किए गए आदेश के संदर्भ में बनाए गए दायित्व के रूप में मान्यता प्राप्त होने के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार न्यायालय स्वयं को धारा 7क(1)(क) की व्याख्या करने में असमर्थ पाता है, जो पैरा 20 के आदेश को निराधार बनाता है।

फ. बार्ड ने इस बात पर विवाद नहीं किया कि चिकित्सा उपकरण "औषधि" की परिभाषा में आते हैं और इस प्रकार पैरा 20 के तहत गैर अनुसूचित विनिर्मितियों के दायरे में आएंगे। नतीजतन, केवल इसलिए कि प्रतिवादी ने इन निर्माताओं को एक

विशेष प्रारूप में मूल्य सूची प्रस्तुत करने के लिए नहीं बुलाया, बार्ड पैरा 20 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं होगा। बार्ड किसी भी मामले में यह दावा नहीं कर सकता कि वह पैरा 20 का अनुपालन करने की कानूनी बाध्यता से अनभिज्ञ था। एनपीपीए द्वारा 2017 में जो रिपोर्टिंग तंत्र विकसित किया गया था, वह केवल गैर-अनुसूचित विनिर्मिति की कीमत की निगरानी के कार्य में उनकी सहायता करने के लिए था।

ब. न्यायालय ने यह ध्यान में रखा है कि जहां तक गैर-अनुसूचित विनिर्मिति का संबंध है, एनपीपीए केवल उनकी कीमतों की निगरानी करने की शक्ति का प्रयोग करता है। निर्माताओं की इस श्रेणी को मूल्य नियंत्रण की कठोरता से मुक्त करने के बाद, पूर्णांकीकरण सिद्धांत की प्रयोज्यता को केवल निर्धारित विनिर्मिति तक सीमित करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

भ. न्यायालय को प्रत्यर्थागण द्वारा उठाए गए रुख में कोई औचित्य नहीं दिखता है, जो तर्क देते हैं कि अनुसूचित विनिर्मिति के निर्माता के लिए यह अपने उत्पादों की कीमत को पूरा करने के लिए खुला होगा, लेकिन गैर-अनुसूचित विनिर्मिति

के निर्माताओं को उस लाभ से वंचित किया जाना चाहिए। एक बार एनपीपीए इस निष्कर्ष पर पहुंच गया था कि पूर्णांकन एक सर्वमान्य गणितीय सिद्धांत था, न्यायालय को अनुसूचित और गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों के बीच भेदभाव करने का कोई औचित्य नहीं मिला।

म.गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों के निर्माताओं को पूर्णांकन की सुविधा से वंचित करना, जिसे अन्यथा और आम तौर पर एनपीपीए द्वारा स्वयं एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त गणितीय अभ्यास के रूप में स्वीकार किया जाता है, स्पष्ट रूप से मनमाना होगा। प्रत्यर्थी किसी भी उचित या तर्कसंगत आधार को इंगित करने में विफल रहे हैं जिसके कारण पूर्णांकन का सिद्धांत गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों पर लागू नहीं होगा।"

6. विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा है कि 2013 डीपीसीओ में यह परिकल्पना नहीं की गई है कि गैर-अनुसूचित विनिर्मित मूल्य नियंत्रण की कठोरता के अधीन हैं। यह देखा गया कि 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 में विचार किया गया है कि गैर-अनुसूचित विनिर्मित का एमआरपी बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाना है और यह शर्त के अधीन है कि वार्षिक वृद्धि 10% से अधिक नहीं होगी, और यदि यह 10% से अधिक हो जाती है, तो निर्माता को एमआरपी को डीपीसीओ के तहत स्वीकार्य एमआरपी पर वापस लाना होगा और

अगले बारह (12) महीनों के लिए इसे उसी स्तर पर रखना होगा। 2013 डीपीसीओ का पैरा 20 केवल सरकार पर यह निगरानी रखने का दायित्व डालता है कि गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों की एमआरपी एक वर्ष में 10% से अधिक न बढ़े।

7. विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी देखा कि उपरोक्त नुस्खे के उल्लंघन के परिणामों को अटकलों के लिए खुला नहीं छोड़ा गया है और 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 में स्पष्ट और सुस्पष्ट शब्दों में दंड के साथ-साथ उपचारात्मक उपाय भी निर्धारित किए गए हैं जिन्हें निर्माताओं और सरकार द्वारा अपनाया जाना चाहिए। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 में अतिप्रभारित के मामले में किसी औषधि की एमआरपी को सालाना बढ़ाने के अधिकार से वंचित करने की परिकल्पना नहीं की गई है। न्यायालय प्रावधान में प्रयुक्त "पूर्ववर्ती" और "अगले" शब्दों को ध्यान में रखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा। आगे यह देखा गया कि अतिप्रभारित के मामले में, जिस अवधि के दौरान निर्माता द्वारा एमआरपी को संशोधित और संरक्षित किया जाना चाहिए, वह उल्लंघन की तारीख से अगले बारह महीने निर्धारित है। माना गया कि उल्लंघन की तारीख वह तारीख नहीं है जिस दिन निर्माता को डिमांड नोटिस भेजा गया था, बल्कि वह तारीख थी जब एमआरपी निर्धारित अनुमेय 10% सीमा से अधिक बढ़ गई थी।

8. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा यह देखा गया कि ऐसे मामले में जहां कई वर्षों के बाद कोई उल्लंघन पाया जाता है, वास्तविक दायित्व पर पहुंचने के लिए, प्राधिकारी को कानूनी रूप से स्वीकार्य एमआरपी का पता लगाने के लिए पीछे की ओर गणना करनी होगी जिसे लागू किया जाना है और बारह महीने की अवधि जिसके दौरान उस एमआरपी को संरक्षित किया जाना चाहिए।

9. विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे कहा कि 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 और औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (1995 डीपीसीओ) के पैरा 13 (पैरा 13) में काफी अंतर है। यह नोट करता है कि बाद वाला उस तारीख से ब्याज का भुगतान करने की परिकल्पना करता है जब कोई निर्माता मांग सूचना का पालन करने में विफल रहता है, जबकि पहला आदेश देता है कि अतिप्रभारित लेने की तारीख से अतिप्रभारित वाली राशि पर ब्याज का भुगतान किया जाता है।

10. विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि एनपीपीए केवल गैर-अनुसूचित विनिर्मिति के एमआरपी की निगरानी करने की शक्ति का प्रयोग करता है। इस प्रकार, यह देखा गया कि पूर्णांकन सिद्धांत की प्रयोज्यता को केवल अनुसूचित विनिर्मितियों तक सीमित करने का कोई औचित्य नहीं था। एक बार जब एनपीपीए ने यह निष्कर्ष निकाल लिया कि पूर्णांकन एक सर्वमान्य गणितीय सिद्धांत है, तो इस सिद्धांत को अनुसूचित और गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों पर भेदभावपूर्ण तरीके से लागू करने का कोई कारण नहीं है। सिद्धांत को लागू

करने के लिए गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों के निर्माताओं को वंचित करना विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा स्पष्ट रूप से मनमाना माना गया था।

11. यह उपरोक्त पृष्ठभूमि में है कि भारत संघ और एनपीपीए ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें कहा गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 की व्याख्या में गलती की है और इसके पीछे के सच्चे इरादे को पाने में विफल रहे हैं, जिसमें अपीलार्थियों का कहना है कि उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना सर्वोपरि है। अपीलार्थियों ने स्पष्ट किया है कि वे तत्काल एलपीए में निर्माता द्वारा अधिक प्रभार के लिए देय ब्याज के संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों को चुनौती नहीं दे रहे हैं।

12. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित केंद्र सरकार के स्थायी वकील श्री कीर्तिमान सिंह ने कहा कि 2013 डीपीसीओ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 ('ईसी अधिनियम') की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है। जिसके शीर्षक में लिखा है, 'आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण आदि को नियंत्रित करने की शक्तियाँ'। उनका मानना है कि ईसी अधिनियम की अनुसूची के आइटम नंबर 1 के संदर्भ में औषधि ' एक आवश्यक वस्तु है। श्री सिंह का मानना है कि आवश्यक औषधियों और औषधियों की खरीद और उपलब्धता से संबंधित मामलों में, उपभोक्ता/जनता का हित सर्वोपरि है, और नियामक व्यवस्था को तदनुसार

समझा जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया कि लोक/उपभोक्ता हित का तत्व ईसी अधिनियम और 2013 डीपीसीओ का व्यापक और सर्वव्यापी तत्व है। इस दलील के समर्थन में, वह मीनाक्षी मिल्स बनाम भारत संघ (1974) 1 एससीसी 468 और प्राग आइस एंड ऑयल मिल्स बनाम भारत संघ (1978) 3 एससीसी 459 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर भरोसा करते हैं, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादक द्वारा अर्जित मुनाफाखोरी और राजस्व को रखा नहीं जा सकता है, यह सर्वोपरि विचार नहीं है और ऐसा करने से उचित मूल्य पर वस्तु के समान वितरण और उपलब्धता का तत्व नष्ट हो जाएगा, जो अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य के लिए विपरीत होगा।

13. श्री सिंह भारत संघ बनाम साइनामाइड इंडिया, (1987) 2 एससीसी 720 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हैं, जिसमें, न्यायालय ने औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के तहत एक मामले पर विचार करते हुए जीवन रक्षक औषधियों जैसे दुर्लभ संसाधनों में मुनाफाखोरी को 'द्वेषपूर्ण' के रूप में संदर्भित किया, जिन्हें बंधित करने और नियंत्रित करने की आवश्यकता है। उक्त निर्णय के बाद शीर्ष न्यायालय ने ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन बनाम भारत संघ, (2014) 2 एससीसी 753 मामले में कहा कि डीपीसीओ के तहत मूल्य निर्धारण एक विधायी उपाय की प्रकृति में है, जिसका प्रमुख उद्देश्य उचित मूल्य पर वस्तुओं का समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करना है। यह प्रस्तुत किया गया था कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन (पूर्वोक्त) में निर्णय का

पालन भारत संघ बनाम सीआईपीएलए (2017) 5 एससीसी 262 में किया गया है।

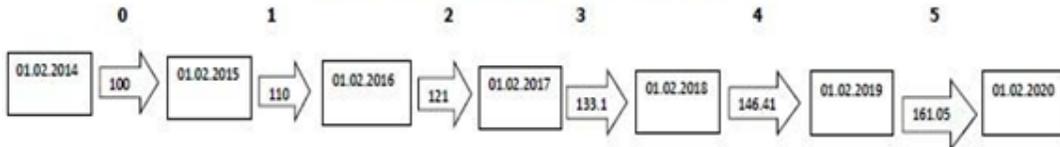
14. श्री सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त निर्णय दृढ़ता से स्थापित करते हैं कि अपीलकर्ता न केवल सशक्त हैं, बल्कि 2013 डीपीसीओ और ईसी अधिनियम के अंतर्निहित उद्देश्य और सर्वव्यापी आधार को ध्यान में रखते हुए 2013 डीपीसीओ के प्रावधानों को लागू करने के लिए बाध्य हैं, जो यह सुनिश्चित करके उपभोक्ता हित को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना है कि जीवन रक्षक औषधियों को समान रूप से वितरित किया जाए और उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाए। इसलिए वह प्रस्तुत करते हैं कि 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 का उद्देश्य निर्माताओं द्वारा अनुचित मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाना है जो जनता/उपभोक्ता के हितों के लिए हानिकारक होगा।

15. श्री सिंह ने आगे कहा कि गैर-अनुसूचित औषधि ईसी अधिनियम और 2013 डीपीसीओ के तहत स्थापित मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के दायरे से बाहर नहीं हैं और पैरा 20 का उद्देश्य निर्माताओं को उपभोक्ताओं/जनता के हितों के विपरीत काम करने से रोकना है। यह उनका निवेदन है कि यह तथ्य कि पैरा 20 को 2013 डीपीसीओ में जगह मिली है, यह एक संकेतक है कि गैर-अनुसूचित औषधियों को मूल्य नियंत्रण व्यवस्था से बाहर निकालने का इरादा नहीं था। वह प्रस्तुत करता है कि भले ही सरकार द्वारा गैर-अनुसूचित औषधि के लिए कोई एमआरपी तय और संशोधित नहीं किया गया हो, इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि यह मूल्य नियंत्रण तंत्र के अधीन नहीं है। उनका

कहना है कि पैरा 20 के तहत एमआरपी की निगरानी करने की सरकार की शक्ति का अर्थ है कि अनुसूचित विनिर्मिति मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं।

16. श्री सिंह ने इस न्यायालय का ध्यान एक उदाहरण की ओर आकर्षित किया है, जिसमें बताया गया है कि 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 के अनुसार गैर-अनुसूचित विनिर्मिति की एमआरपी कैसे बढ़ जाती है, यदि कोई उल्लंघन नहीं होता है। यह चित्रण को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

पैरा 20, डी. पी. सी. ओ. की शर्तों में स्थायी वृद्धि

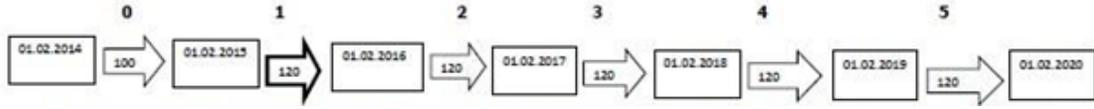


उनका कहना है कि ऐसी स्थिति में जहां एक गैर-अनुसूचित विनिर्मिति की एमआरपी 01.02.2014 में 100 रुपये है, तो विनिर्माता बारह महीने के बाद, यानी 01.02.2015 को ऐसे गैर-अनुसूचित विनिर्मिति की एमआरपी को 110 रुपये तक बढ़ाने का हकदार है। इसी प्रकार, विनिर्माता ऐसे गैर-अनुसूचित विनिर्मिति की एमआरपी को 01.02.2016 में 121 रुपये तक बढ़ाने का हकदार है और इसी तरह, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। उनका मानना है कि 2013 डीपीसीओ का पैरा 20 इसी तरह कार्य करने का इरादा रखता है।

17. 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 को आदर्श रूप से संचालित करने के तरीके पर प्रकाश डालने के बाद, श्री सिंह ने अपीलार्थियों के अनुसार, 2013 डीपीसीओ

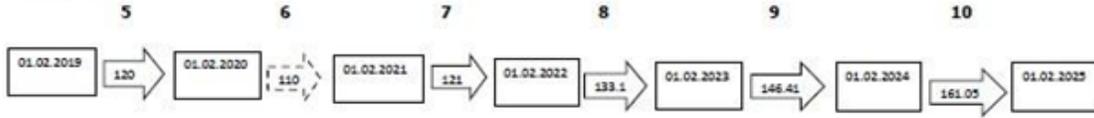
के पैरा 20 के उल्लंघन के परिणामों को दिखाने के लिए एक चार्ट पर भरोसा किया है, जिसे नीचे दिया गया है:

वर्णन :



उपरोक्त चित्रण में, कंपनी ने वर्ष 1 में पैरा 20, डी. पी. सी. ओ. के संदर्भ में अपनी कीमत में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की है, और इसलिए वर्ष 1 से ही चूक में है।

नतीजतन, जब तक यह चूक ठीक नहीं हो जाती, तब तक कंपनी पैरा 20 का उल्लंघन करती रहेगी। पैरा 20 के संदर्भ में, घड़ी को चूक के वर्ष में वापस सेट किया जाएगा और कंपनी को अगले एक वर्ष के लिए अनुमेय मूल्य बनाए रखने की आवश्यकता हो सकती है। उपरोक्त उदाहरण में, यदि कंपनी द्वारा वर्ष 6 में चूक को ठीक कर दिया जाता है, तो उसे वर्ष 1 की कीमत पर वापस जाना होगा और अगले एक वर्ष के लिए इसे बनाए रखना होगा। इसे निम्नलिखित चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है:



18. श्री सिंह प्रस्तुत करते हैं कि जिस तरह से 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 में इस्तेमाल किए गए शब्दों 'पूर्ववर्ती' और 'अगला' की व्याख्या विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई है, वह गलत है। चार्ट का उल्लेख करते हुए श्री सिंह प्रस्तुत करते हैं कि यदि किसी विशेष गैर-अनुसूचित विनिर्मिति का एमआरपी 01.02.2014 को रु. 100/- निर्धारित है और यदि 01.02.2015 में ऐसे गैर-अनुसूचित विनिर्मिति की एमआरपी रु.110/- तक बढ़ाने के बजाय, निर्माता द्वारा इसे रु.120/- तय किया गया है और 01.02.2020 तक ऐसे गैर-अनुसूचित विनिर्मिति की एमआरपी में कोई और वृद्धि नहीं हुई है, फिर यदि उल्लंघन 01.02.2020 में पाया जाता है, तो उस तारीख से, यानी 01.02.2020

से, निर्माता को ऐसे गैर-अनुसूचित विनिर्मिति की एमआरपी को रु.110/- के रूप में वापस करना होगा। अर्थात्, 01.02.2015 के लिए एमआरपी में वृद्धि अनुज्ञेय है, और इसे 01.02.2021 तक उक्त एमआरपी पर बनाए रखना होगा। उन्होंने आगे कहा कि निर्माता उन पांच वर्षों के लिए 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 के लाभ का हकदार नहीं होगा, जहां औषधि की एमआरपी में वृद्धि नहीं हुई है, यानी 01.02.2015 से 01.02.2020 तक। उनका कहना है कि 01.02.2020 में अपराध का पता चलने के बाद एम.आर.पी. को वापस 110 रुपये कर दिया गया है। विनिर्माता केवल 01.02.2021 से ऐसे गैर-अनुसूचित विनिर्मिति की एमआरपी को रु.110 /- के 10% यानी रु.121 तक बढ़ाने का हकदार होगा।

19. श्री सिंह आगे प्रस्तुत करते हैं कि 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 के तहत कोई अधिकार पर विचार नहीं किया गया है और यह केवल एक प्रतिबंध पर विचार करता है। उन्होंने एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स, 2019 एससीसी ऑनलाइन 7040 में इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले पर भरोसा किया, जो इस प्रस्तुतिकरण का समर्थन करता है। उनका कहना है कि उक्त मामले में, यह देखा गया है कि 2013 डीपीसीओ का पैरा 20 विनिर्माता पर केवल पैरा 20 में निर्धारित औषधियों की एमआरपी बढ़ाने के लिए प्रतिबंध लगाता है।

20. श्री सिंह ने दृढ़तापूर्वक कहा है कि 2013 डीपीसीओ का पैरा 20 दंडात्मक प्रकृति का है। उनका तर्क है कि यदि कोई विनिर्माता 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 की अनुज्ञेय सीमा से अधिक गैर-अनुसूचित विनिर्मिति की एमआरपी बढ़ाता है तो तीन दंडात्मक परिणाम होंगे। सबसे पहले, विनिर्माता को एमआरपी को अनुज्ञेय स्तर तक कम करने की आवश्यकता होगी; दूसरे, एमआरपी में वृद्धि की तारीख से अधिक वसूली गई राशि को "...जुर्माना के अतिरिक्त" जमा करना आवश्यक होगा; और तीसरा, एमआरपी में वृद्धि की तारीख से अधिक वसूली गई राशि पर ब्याज "...जुर्माना के अतिरिक्त" जमा करना आवश्यक होगा। उनका कहना है कि यदि किसी निर्माता को अनुज्ञेय सीमा से अधिक एमआरपी वसूलने से लाभ होने के बाद भी एमआरपी बढ़ाने की अनुमति दी जाती है, तो 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 के पीछे का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

21. श्री सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि "पूर्णांकन" की अवधारणा वास्तव में औषधियों की कीमतों पर लागू नहीं होती है। उनका कहना है कि कानूनी मापविज्ञान (पैकेज्ड वस्तुएं) नियम, 2011 ("एलएमपीसी नियम") का नियम 2 (एम) "खुदरा बिक्री मूल्य" को परिभाषित करता है और इसमें पूर्णांकन का नियम भी शामिल है। जिसमें 50 पैसे से कम की राशि को पिछले रुपये में पूर्णांकित किया जाता है और 50 पैसे से 95 पैसे के बीच की राशि को पचास पैसे में पूर्णांकित किया जाता है। इसके बाद वह एलएमपीसी नियमों के अध्याय

✓ को संदर्भित करता है, जिसमें नियम 26 2013 डीपीसीओ के तहत अनुसूचित और गैर-अनुसूचित विनिर्मिति के लिए इन नियमों की प्रयोज्यता से छूट देता है। उनका कहना है कि एनपीपीए की दिनांक 12.04.2016 की बैठक के कार्यवृत्त के पैराग्राफ 5.2 पर गैर-अनुसूचित विनिर्मिति पर पूर्णांकन के सिद्धांत को लागू करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह केवल अनुसूचित विनिर्मिति के लिए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में बदलाव के कारण एमआरपी में वृद्धि से संबंधित है। उनका कहना है कि पैरा 5.2 किसी निर्माता को अधिकार के रूप में एमआरपी को पूर्णांकित करने का अधिकार नहीं देता है और अन्यथा भी, पूर्णांकन का लाभ केवल दो दशमलव बिंदुओं तक ही दिया जाता है। उन्होंने जोरदार तर्क दिया कि ऑब्सर्ज बायोटेक लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2020 एससीसी ऑनलाइन डेल 1744 में इस न्यायालय के फैसले पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस तथ्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है कि अनुसूचित विनिर्मितियों के लिए पूर्णांकन का लाभ केवल अधिकतम दो दशमलव अंकों तक ही दिया जाता है, जिसे न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था और इसके अलावा ऑब्सर्ज बायोटेक (पूर्वोक्त) में फैसले को इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने एलपीए संख्या 310/2020 में 20.10.2020 दिनांकित आदेश के तहत रोक दिया है।

22. इस न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णयों और उनमें दिए गए तर्कों का समर्थन करते हैं और उन पर भरोसा करते हैं।

23. पक्षकारों के लिए विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख पर दस्तावेजों और सामग्री को ध्यान से परिशीलन किया ।

24. इस समय औषधियों ' से संबंधित मूल्य नियंत्रण व्यवस्था की एक संक्षिप्त रूपरेखा देना उचित होगा जैसा कि विभिन्न कानूनों, आदेशों और नीतियों के माध्यम से स्थापित किया गया है। 1955 में, भारत की संसद ने कुछ आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और मूल्य निर्धारण को नियंत्रित करने के लिए इसी अधिनियम पारित किया। इसी अधिनियम की धारा 2ए, "आवश्यक वस्तु" को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है इसी अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुएं, जिसमें अनुसूची में वस्तु संख्या 1 के रूप में औषधि' (औषधि और कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 3 (बी) के तहत परिभाषित) को शामिल किया गया है।

25. आवश्यक वस्तु (इसी) अधिनियम की धारा 3 केंद्र सरकार को उस आशय का आदेश पारित करके उस कीमत को नियंत्रित करने की शक्ति देती है जिस पर एक आवश्यक वस्तु खरीदी या बेची जा सकती है। उक्त प्रावधान के प्रासंगिक उद्धरण निम्नानुसार हैं:

"3. आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण आदि को नियंत्रित करने की शक्तियाँ- (1) यदि केंद्र सरकार की राय है कि किसी आवश्यक वस्तु की आपूर्ति को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए या उचित मूल्यों पर उनके समान वितरण और

उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह आदेश द्वारा उसके उत्पादन, आपूर्ति और वितरण और व्यापार और वाणिज्य को विनियमित या प्रतिबंधित करने का प्रावधान कर सकती है।

(2) उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके तहत किया गया आदेश प्रदान कर सकता है -

(ग) उस कीमत को नियंत्रित करने के लिए जिस पर किसी भी आवश्यक वस्तु को खरीदा या बेचा जा सकता है।

26. औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1963 को भारत रक्षा अधिनियम, 1915 के तहत केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रख्यापित किया गया। हालाँकि, 1966, 1970, 1979, 1987 और 1995 में अधिसूचित औषधि मूल्य नियंत्रण आदेशों की अगली श्रृंखला इसी अधिनियम की धारा 3 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित किया गया।

27. 1995 डीपीसीओ को भारत की औषधि नीति 1994 के आलोक में अधिसूचित किया गया था। 1995 डीपीसीओ के तहत परिकल्पित मूल्य निर्धारण तंत्र में औषधि विनिर्मिति के उत्पादन की लागत को ध्यान में रखा

गया था, जिसमें उत्पादन के बाद के खर्चों से संबंधित भत्ते को भी ध्यान में रखा गया था। 48 पृष्ठों में से पृष्ठ 20 पृष्ठों में औषधि जिन्हें "अनुसूचित थोक औषधि " के रूप में परिभाषित किया गया था और उसी पर आधारित विनिर्मिति को "अनुसूचित विनिर्मिति" के रूप में परिभाषित किया गया था। 1995 डीपीसीओ ने सरकार को "अनुसूचित" और "गैर-अनुसूचित" थोक औषधियों और विनिर्मितियों दोनों की कीमत तय करने और संशोधित करने की शक्ति प्रदान की।

28. 1995 डीपीसीओ का पैरा 13 किसी निर्माता द्वारा नोटिस के माध्यम से अतिप्रभारित राशि की वसूली करने की सरकार की शक्ति से संबंधित है। 1995 डीपीसीओ का पैरा 13 इस प्रकार है:

13. मौजूदा निर्माताओं के लिए निर्धारित विनिर्मितियों की कीमत.- (1) अनुसूचित विनिर्मिति के सभी मौजूदा निर्माता, ब्रांडेड या जेनेरिक या अनुसूचित विनिर्मिति के दोनों संस्करणों को अधिकतम कीमत (साथ ही लागू स्थानीय कर) से अधिक कीमत पर बेचते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित और अधिसूचित, ऐसे सभी विनिर्मिति की कीमतों को संशोधित किया जाएगा जो कि अधिकतम कीमत (साथ ही लागू स्थानीय कर) से अधिक नहीं होगी।

बशर्ते, अधिकतम कीमत की अधिसूचना की तारीख से पहले बाजार में उत्पादित या उपलब्ध अनुसूचित विनिर्मिति के मामले में, निर्माता ऐसी अधिसूचना की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे अनुसूचित विनिर्मिति की अधिकतम खुदरा कीमत अधिकतम कीमत (साथ ही लागू स्थानीय कर) से अधिक न हो।

(2) अनुसूचित विनिर्मितियों के सभी मौजूदा निर्माता, ब्रांडेड या जेनेरिक या अनुसूचित विनिर्मिति के दोनों संस्करणों को सरकार द्वारा निर्धारित और अधिसूचित अधिकतम कीमत (लागू स्थानीय करों के अलावा) से कम कीमत पर बेचते हैं, उन्हें अपनी मौजूदा अधिकतम खुदरा कीमत बनाए रखनी होगी।

(3) अधिकतम खुदरा मूल्य में वार्षिक वृद्धि पैराग्राफ 16 के उप-पैराग्राफ (2) और (3) के प्रावधान के अनुसार पिछले वर्ष के संबंध में थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि के अनुसार की जा सकती है।

बशर्ते कि थोक मूल्य सूचकांक में गिरावट की स्थिति में, कीमतों में तदनुरूप कटौती पैराग्राफ 16 के उप पैराग्राफ (4) के प्रावधान के अनुसार की जाएगी।

29. इसके बाद 2012 में, सरकार ने राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल्स मूल्य निर्धारण नीति 2012 ("एनपीपीपी 2012") की घोषणा की, जिसमें एनपीपीपी 2012 को तैयार करने वाले प्रमुख सिद्धांतों को एनपीपीपी 2012 के पैरा 3 में बताया गया है, जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"3. राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण नीति 2012 के प्रमुख सिद्धांत

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति 2012 में कीमतों के विनियमन के लिए प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार है:

- (1) औषधियों की अनिवार्यता
- (2) केवल विनिर्मिति की कीमतों का नियंत्रण
- (3) बाजार आधारित मूल्य निर्धारण "

30. एनपीपीपी 2012 का पैरा 4 एनपीपीपी 2012 के तहत औषधियों के मूल्य नियंत्रण और निर्धारण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों की रूपरेखा देता है, जिसके प्रासंगिक उद्धरण निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

"4. एनपीपीपी-2012 में औषधि मूल्य नियंत्रण और निर्धारण के सिद्धांत

(i) मूल्य विनियमन औषधि की 'अनिवार्यता' के आधार पर होगा जैसा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा घोषित 'आवश्यक औषधियों की राष्ट्रीय सूची - 2011' में निर्धारित है, और औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के तहत सार्वजनिक हित में समय-समय पर संशोधित किया गया है।

(ii) मूल्य विनियमन केवल विनिर्मिति पर लागू किया जाएगा, यानी

वास्तव में उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली औषधि, न कि किसी अपस्ट्रीम उत्पाद जैसे कि थोक औषधियाँ और मध्यवर्ती पर लागू होगा।

(iii) मूल्य नियंत्रण का दायरा एनएलईएम-2011 में सूचीबद्ध खुराक और शक्तियों के अनुसार होगा।

(iv) एनएलईएम औषधियों की अधिकतम कीमत तय करने की पद्धति, उस औषधि के कुल बाजार कारोबार के 1% से अधिक और उसके बराबर बाजार हिस्सेदारी वाले सभी ब्रांडों की सरल औसत कीमत को अपनाकर (चालू वार्षिक कारोबार के आधार पर) निम्नलिखित नियम के अनुसार अपनाई जाएगी। (औषधि के कुल बाजार कारोबार के 1% से अधिक और उसके बराबर बाजार हिस्सेदारी वाली औषधि के सभी ब्रांडों की कीमतों का योग)। (औषधि के ऐसे ब्रांड का उत्पादन करने वाले निर्माताओं की कुल संख्या)।

(v) विनिर्मितियों की कीमत केवल अधिकतम कीमत (सीपी) तय करके की जाएगी। निर्माता अपने उत्पादों के लिए सीपी के बराबर या उससे नीचे किसी भी कीमत तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। सीपी को खुराक के आधार पर तय किया जाएगा, जैसे कि

NLEM-2011 में सूचीबद्ध प्रति टैबलेट कैप्सूल मानक इंजेक्शन मात्रा के आधार पर।

(vi) अधिकतम कीमत आसानी से निगरानी योग्य बाजार आधारित डाटा (एमबीडी) के आधार पर तय की जाएगी। आरंभ करने के लिए, इस आसानी से निगरानी योग्य बाजार डाटा का आधार फार्मास्यूटिकल्स बाजार डाटा विशेषज्ञ कंपनी-आईएमएस हेल्थ (आईएमएस) के पास डाटा उपलब्ध होगा। जहां भी आवश्यकता होगी, इस डाटा की जांच राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा उचित सर्वेक्षण मूल्यांकन द्वारा की जाएगी। चूंकि आईएमएस डाटा स्टॉकिस्ट स्तर की कीमतों के लिए मूल्य आंकड़े देता है, इसलिए अधिकतम कीमत (जो कि अधिकतम खुदरा मूल्य होगा) पर पहुंचने के लिए, खुदरा विक्रेता के लिए मार्जिन के रूप में आईएमएस कीमत में 16% की बढ़ोतरी की जाएगी ताकि उपभोक्ताओं से उचित अधिकतम कीमत वसूल की जा सके।

(vii) आईएमएस डाटा में नहीं आने वाली औषधियों के लिए, एनपीपीए इसकी शुरुआत करके डाटा एकत्र करेगा

(viii) उन औषधियों के लिए जहां प्रतिस्पर्धा के अभाव के कारण कीमत में कोई कमी नहीं है, अन्य खुराक और शक्ति के साथ एक ही अणु की कीमत में समग्र प्रतिशत की कमी लागू की जाएगी; अन्यथा एक ही चिकित्सीय श्रेणी में औषधियों की कीमत में समग्र प्रतिशत की कमी लागू की जाएगी।

(ix) एनएलईएम में सूचीबद्ध औषधि के लिए सीपी नई राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल मूल्य निर्धारण नीति की घोषणा की तारीख से छह महीने पहले आईएमएस डाटा के आधार पर गणना की गई कीमतों का सरल औसत होगा यानी नई नीति को प्रभाव में लाने के लिए नियत तिथि। एक ऐसी औषधि के लिए जिसका डाटा आईएमएस में उपलब्ध नहीं है, एनपीपीए नियत तिथि से छह महीने पहले प्रचलित कीमतों के आधार पर सरल औसत मूल्य निर्धारित करने के लिए उचित समय के भीतर डाटा शुरू करेगा। इस प्रकार आईएमएस डाटा में उपलब्ध और एनपीपीए द्वारा एकत्र की गई औषधियों के लिए सरल औसत मूल्य डाटा तिथि समान होगी। एक बार साधारण औसत मूल्य तय हो जाने के बाद, एनपीपीए एक उचित कार्य पद्धति और प्रणाली के माध्यम से निरंतर आधार पर इसके कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।

(x) इन एनएलईएम-2011 औषधियों की कीमतों में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा अधिसूचित थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार वार्षिक वृद्धि की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल को संदर्भ तिथि के रूप में निर्धारित करने का प्रस्ताव है। तदनुसार, हर साल 1 अप्रैल को, कंपनियां पिछले वर्ष के लिए थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि की सीमा तक अपनी कीमतों को संशोधित करने के लिए स्वचालित रूप से अधिकृत होंगी। थोक मूल्य सूचकांक में गिरावट की स्थिति में, अधिकतम कीमत में तदनुरूप कमी अनिवार्य होगी। एनपीपीए स्वयं भी प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को लागू होने वाली संशोधित अधिकतम कीमतों को अलग से अधिसूचित करेगा, और यदि

किसी कंपनी ने संशोधित अधिकतम कीमतों के अनुरूप कीमतें तय नहीं की हैं, तो एनपीपीए इन्हें संशोधित करने के लिए उचित कार्रवाई करेगा।

(xi) बाजार में हिस्सेदारी रखने वाली औषधि के सभी ब्रांडों की साधारण औसत कीमत (चालू वार्षिक कारोबार के आधार पर) उस औषधि के कुल बाजार कारोबार के 1% से अधिक और उसके बराबर है साधारण औसत मूल्य की गणना के लिए संदर्भ मूल्य - एमएटी मूल्य में परिवर्तन के कारण वार्षिक आधार पर भी बदल सकते हैं। हालाँकि, एमएटी के आधार पर अधिकतम कीमतों में कोई वार्षिक संशोधन नहीं होगा। एमएटी मूल्य के आधार पर अधिकतम कीमतों में संशोधन पांच साल में केवल एक बार या जब भी एनएलईएम अद्यतन संशोधित किया जाता है, तब किया जाएगा। हालाँकि, यदि 5 वर्षों के बीच भी किसी विशेष औषधि की बाजार संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव होता है तो सरकार एनएलईएम के तहत औषधि की अधिकतम कीमत को संशोधित करेगी।

(xii) गैर-मूल्य नियंत्रण औषधियां मौजूदा मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के तहत, गैर-अनुसूचित औषधियों की कीमतों की निगरानी की जाती है, और यदि ऐसी औषधियों की कीमतें एक वर्ष में 10% से अधिक बढ़ जाती हैं, तो कुछ मानदंडों के अधीन, सरकार इन औषधियों की कीमतें समय-समय पर तय करती है। प्रस्तावित नीति में सभी आवश्यक औषधियां मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं। इससे यह होगा कि गैर-आवश्यक

औषधियां नियंत्रित व्यवस्था के तहत नहीं होनी चाहिए और उनकी कीमतें बाजार ताकतों द्वारा तय की जानी चाहिए। हालाँकि, समग्र औषधि की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए, यह प्रस्तावित है कि ऐसी औषधियों की कीमतों की नियमित आधार पर निगरानी की जाए, और जहां प्रति वर्ष 10% से अधिक की दर से ऐसी कीमत में वृद्धि देखी जाती है, सरकार को अगले बारह महीनों के लिए इन औषधियों की कीमत को इस सीमा से नीचे रखने का अधिकार होगा।....”

31. उपरोक्त सिद्धांतों को पढ़ने से पता चलता है कि एनपीपीपी 2012 के तहत औषधियों का मूल्य विनियमन एक औषधि की "अनिवार्यता" के आधार पर होगा, जो आवश्यक औषधियों की राष्ट्रीय सूची, 2011 ("एनएलईएम") के आधार पर निर्धारित किया गया था और औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया था। 1995 डीपीसीओ के विपरीत, मूल्य विनियमन केवल विनिर्मितियों पर लागू किया जाएगा, न कि थोक औषधियों पर। एनपीपीपी 2012 के पैरा 4 के बिंदु (iii) से (xi) उस पद्धति और तरीके का वर्णन करते हैं जिसके आधार पर एनएलईएम में सूचीबद्ध औषधियों के आधार पर विनिर्मिति की कीमतें निर्धारित की जाएंगी। एनपीपीपी 2012 के पैरा 4(xii) में कहा गया है कि "गैर-आवश्यक" औषधियों या औषधियों के लिए जो एनएलईएम में शामिल नहीं हैं, कोई नियंत्रित व्यवस्था नहीं होगी और उनकी कीमतें बाजार मांग द्वारा तय की जाएंगी। हालाँकि, सरकार ऐसी औषधियों की कीमत की निगरानी करेगी ताकि

यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी "गैर-आवश्यक" औषधियों की कीमत प्रति वर्ष 10% से अधिक न बढ़े, और यदि प्रति वर्ष 10% से अधिक वृद्धि होती है, तो सरकार को अगले 12 महीनों के लिए इन औषधियों की कीमत इस सीमा से कम करने का अधिकार है।

32. केंद्र सरकार ने एनपीपीपी 2012 में लिए गए और निर्धारित नीतिगत निर्णयों को लागू करने के लिए 2013 डीपीसीओ को प्रख्यापित किया है। एनपीपीपी 2012 के बाद, 2013 डीपीसीओ ने थोक औषधियों की कीमत तय करने, विनियमित करने और संशोधित करने की अवधारणा को खत्म कर दिया। 2013 डीपीसीओ केवल अनुसूचित और गैर-अनुसूचित विनिर्मिति से संबंधित है। 2013 डीपीसीओ का पैरा 2(जेडबी) "अनुसूचित विनिर्मिति" को परिभाषित करता है, जिसका अर्थ है कोई भी विनिर्मिति, जो 2013 डीपीसीओ की पहली अनुसूची में शामिल है, चाहे उसे सामान्य संस्करण या ब्रांड नाम से संदर्भित किया गया हो। इसी तरह, 2013 डीपीसीओ के पैरा 2(v) में एक "गैर-अनुसूचित सम्मिश्रण" को परिभाषित किया गया था, जिसका अर्थ एक ऐसा विनिर्मिति है जो 2013 डीपीसीओ की पहली अनुसूची में शामिल नहीं है। 2013 डीपीसीओ की पहली अनुसूची में 2013 डीपीसीओ के पैरा 2(टी) के अनुसार, एनएलईएम में शामिल औषधियों की एक सूची शामिल है। इसलिए, एनएलईएम में शामिल सभी आवश्यक औषधियों को "अनुसूचित सम्मिश्रण" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और सभी "गैर-आवश्यक" औषधियों को 2013 डीपीसीओ के तहत "गैर-अनुसूचित सम्मिश्रण" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

33. वर्तमान में मौजूद औषधि विनिर्मितियों की तुलना में मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के विकास की रूपरेखा तैयार करते हुए, यह न्यायालय अब अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 की व्याख्या से संबंधित मुद्दे से निपटेगा। वर्तमान मामले में विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उठता है वह 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 की व्याख्या है।

34. जैसा कि ऊपर कहा गया है, पैरा 20 को प्रत्यक्ष रूप से पढ़ने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि 2013 डीपीसीओ का पैरा 20 दो अलग-अलग और पहचान योग्य भागों में विभाजित है। पहले भाग में प्रावधान है कि गैर-अनुसूचित विनिर्मिति का निर्माता पिछले बारह महीनों में ऐसे गैर-अनुसूचित विनिर्मिति के एमआरपी में एमआरपी के 10 प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है, अगले बारह महीनों के लिए उक्त एमआरपी को संरक्षित कर सकता है और सरकार पर इस तरह के गैर-अनुसूचित विनिर्मिति के एमआरपी में वृद्धि की निगरानी करने का दायित्व डालता है। 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 का दूसरा भाग एक निर्माता द्वारा किए गए उल्लंघन के परिणामों से संबंधित है, यदि यह बारह महीने की अवधि में गैर-अनुसूचित विनिर्मितिकी एमआरपी को 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ा देता है। इस तरह के उल्लंघन के परिणाम यह होते हैं कि निर्माता अपराध की तारीख से ब्याज के साथ अधिक वसूली गई राशि जमा करने और गैर-अनुसूचित विनिर्मिति की एमआरपी को अगले बारह महीनों (12) के लिए एमआरपी के 10% के स्तर तक कम करने के लिए उत्तरदायी है।

35. 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 को पढ़ने पर, यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उक्त प्रावधान एनपीपीपी 2012 के पैरा 4(xii) पर आधारित किया गया है। एनपीपीपी 2012 के तहत परिकल्पित मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के अनुसार, सरकार द्वारा गैर-अनुसूचित या गैर-आवश्यक विनिर्मितियों को मूल्य नियंत्रण की कठोरता से बाहर करने का एक सचेत निर्णय लिया गया है ताकि गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों के निर्माताओं को बाजार की मांग के अनुसार कीमतें तय करने में सक्षम बनाया जा सके। यह निर्णय लिया गया है कि सरकार केवल इन औषधियों की कीमतों की निगरानी करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गैर-जरूरी औषधियों की कीमत एक वर्ष में 10% से अधिक न बढ़े। इसमें आगे कहा गया है कि जब ऐसी औषधियों की कीमत एक वर्ष में 10% से अधिक की दर से बढ़ती है, तो सरकार को इन औषधियों की कीमत इस सीमा से कम करने का अधिकार है। इस न्यायालय की राय में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 को एनपीपीपी 2012 में परिकल्पित केंद्र सरकार की नीति को प्रभावी बनाने के लिए शामिल किया गया है।

36. इस दिशा में, इस न्यायालय को अपीलार्थियों के इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि गैर-अनुसूचित औषधियां इसी अधिनियम और 2013 डीपीसीओ के तहत स्थापित मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के दायरे से बाहर नहीं हैं। यह निर्विवाद है कि 2013 डीपीसीओ को एनपीपीपी 2012 में बताई गई नीति को प्रभावी करने के लिए प्रख्यापित किया गया है। एनपीपीपी 2012, यह कहने में बहुत स्पष्ट है कि गैर-आवश्यक औषधियां नियंत्रित व्यवस्था के

तहत नहीं हैं और केवल आवश्यक औषधियां ही मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के तहत हैं। 2013 डीपीसीओ की अनुसूची और परिभाषाएँ यह स्पष्ट करती हैं कि 2013 डीपीसीओ के तहत आवश्यक दवाओं/औषधियों और अनुसूचित विनिर्मितियों के बीच कोई अंतर नहीं है। परिणामस्वरूप, इसका मतलब यह होगा कि 2013 डीपीसीओ के तहत गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों एनपीपीपी 2012 के अनुसार गैर-आवश्यक औषधियां हैं। तदनुसार, 2013 डीपीसीओ के तहत गैर-अनुसूचित औषधि विनिर्मिति मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के अधीन नहीं होंगे।

37. मूल्य नियंत्रण व्यवस्था से गैर-अनुसूचित औषधियों का अपवर्जन तब और स्पष्ट हो जाता है जब 2013 डीपीसीओ की तुलना इसके पूर्ववर्ती, 1995 डीपीसीओ से की जाती है। 1995 डीपीसीओ के तहत, सरकार के पास अनुसूचित और गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों के लिए कीमतें तय करने और संशोधित करने की शक्ति थी। गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों के लिए कीमतें तय करने और संशोधित करने की यह शक्ति 2013 डीपीसीओ के तहत समाप्त कर दी गई है, जो सरकार को केवल गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों के एमआरपी में बदलाव की निगरानी करने की शक्ति देती है। यह उपदर्शित करता है कि सरकार ने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था से गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों को बाहर करने के लिए जानबूझकर और सचेत निर्णय लिया। इस प्रकार, अपीलार्थियों का यह निवेदन कि मूल्य नियंत्रण व्यवस्था में शामिल गैर-अनुसूचित औषधियों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है

38. इसलिए, 2013 डीपीसीओ के तहत औषधियों की एमआरपी तय करने और संशोधित करने की सरकार की शक्तियां अनुसूचित विनिर्मितियों तक सीमित हैं और गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों तक विस्तारित नहीं करता हैं। गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों के संबंध में, सरकार के पास केवल एमआरपी वृद्धि की निगरानी करने की शक्ति है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक वर्ष में इसमें 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि न हो, और यदि एक वर्ष में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होती है, तो इसके दंडात्मक परिणाम होते हैं जो 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 में ही निर्धारित किए गए हैं।

39. अपीलार्थियों का मामला है कि 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 का निर्वचन इस तरह से किया जाना चाहिए जहां उपभोक्ता/लोक हित को सर्वोपरि माना जाए। यह तर्क देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मीनाक्षी मिल्स (उपरोक्त), प्राग आइस (उपरोक्त), साइनामाइड इंडिया उपरोक्त, ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन (उपरोक्त) और सीआईपीएलए (उपरोक्त) मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया गया। इसी अधिनियम और 2013 डीपीसीओ का उद्देश्य उचित मूल्य पर औषधियों जैसी आवश्यक वस्तुओं का समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करना था, और ऐसी वस्तुओं की मुनाफाखोरी की अनुमति नहीं दी

जा सकती, अन्यथा ईसी अधिनियम और 2013 डीपीसीओ का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

40. निर्विवाद रूप से, 2013 डीपीसीओ को जनता के हित को ध्यान में रखते हुए और उचित मूल्य पर औषधियों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था। यह अपीलार्थी का मामला नहीं है कि 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 के तहत प्रदान की गई व्यवस्था सरकार को गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों के एमआरपी की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने की शक्ति देती है कि कोई विनिर्माता ऐसे विनिर्मितियों के एमआरपी को 10 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाता है, लोक उपभोक्ता हित को सर्वोपरि ध्यान नहीं देता है। अपीलार्थियों का मामला यह भी नहीं है कि केवल मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लोक उपभोक्ता हित पर सर्वोपरि ध्यान देती है और मूल्य निगरानी प्रणाली ऐसा नहीं करती है। इस न्यायालय की सुविचारित राय में, 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 के तहत परिकल्पित मूल्य निगरानी प्रणाली को लोक उपभोक्ता हित को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है, और अपीलार्थी इसके विपरीत स्थापित करने में विफल रहे हैं।

41. किसी भी स्थिति में, इस न्यायालय ने अपीलार्थियों द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णयों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है और उसकी राय है कि वे वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं। उपरोक्त मामलों में दिए

गए निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न नियंत्रण आदेशों से संबंधित हैं। अपीलार्थी द्वारा भरोसा किए गए सभी मामलों में, नियंत्रण आदेश स्पष्ट रूप से सरकार को संबंधित आवश्यक वस्तु की कीमतें तय करने/संशोधित करने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसके अलावा, साइनामाइड इंडिया (पूर्वोक्त) में निर्णय, जो औषधि (मूल्य नियंत्रण आदेश), 1979("1979 डीपीसीओ") से संबंधित थे और ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन (उपरोक्त) और सीआईपीएलए (पूर्वोक्त) में निर्णय, वर्तमान मामले से अलग हैं क्योंकि 2013 डीपीसीओ स्पष्ट रूप से गैर-अनुसूचित औषधियों के लिए एमआरपी या अधिकतम मूल्य तय करने की शक्ति को बाहर करता है। 1979 डीपीसीओ और 1995 डीपीसीओ दोनों ने सरकार को अनुसूचित और गैर-अनुसूचित थोक औषधियों और विनिर्मितियों दोनों के लिए एमआरपी या अधिकतम कीमत तय करने की शक्ति दी, और उनमें से किसी में भी गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों के एमआरपी की निगरानी करने की शक्ति शामिल नहीं थी। दूसरी ओर 2013 डीपीसीओ विशेष रूप से कहता है कि यह केवल औषधि निर्माण से संबंधित है न कि प्रपुंज औषधि से। इसके अलावा, यह केवल सरकार को अनुसूचित विनिर्मिति के लिए एमआरपी तय करने की शक्ति प्रदान करता है और केवल सरकार को गैर-अनुसूचित विनिर्मिति के एमआरपी की निगरानी करने की अनुमति देता है। इसके लिए उपरोक्त कारणों से, इस न्यायालय की राय है कि

उपरोक्त निर्णयों पर अपीलार्थियों द्वारा रखी गई निर्भरता गलत है और अपीलार्थियों के मामले में सहायता नहीं करती है।

42. अपीलार्थियों का यह भी तर्क है कि 2013 डीपीसीओ का पैरा 20 दंडात्मक प्रकृति का है। उनका मामला यह है कि यदि कोई विनिर्माता 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 की अनुज्ञेय सीमा से अधिक गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों के एमआरपी को बढ़ाता है तो तीन दंडात्मक परिणाम सामने आते हैं जो इस प्रकार हैं: सबसे पहले, विनिर्माता को एमआरपी को अनुज्ञेय स्तर तक कम करना होगा; दूसरा, उसे एमआरपी में वृद्धि की तारीख से अधिभारित राशि जमा करनी होगी "... जुर्माने के अलावा"; और तीसरा, उसे जुर्माने के अलावा एमआरपी में वृद्धि की तारीख से अतिप्रभारित राशि पर ब्याज जमा करना होगा। अपीलार्थियों का तर्क इस आधार पर आधारित है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा "पूर्ववर्ती" और "अगला" शब्दों की गलत व्याख्या की गई है। यह उनका तर्क है कि 'पूर्ववर्ती' शब्द की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि इसका अर्थ उल्लंघन के बिंदु से तुरंत पहले के बारह महीने हो, जबकि 'अगला' शब्द का अर्थ उस बिंदु से बाद के बारह महीने है जहां विनिर्माता एमआरपी को वापस लेता है, न कि उल्लंघन के बिंदु के संदर्भ में।

43. जैसा कि इस न्यायालय ने ऊपर कहा है, 2013 डीपीसीओ का पैरा 20 दो भागों में विभाजित है। पहले भाग में प्रावधान है कि एक गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों का निर्माता पिछले बारह महीनों के दौरान ऐसे गैर-अनुसूचित

विनिर्मितियों के एमआरपी को एमआरपी के 10% तक बढ़ा सकता है, अगले बारह महीनों के लिए उक्त एमआरपी को संरक्षित कर सकता है और सरकार पर ऐसे गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों की एमआरपी में वृद्धि की निगरानी करने का दायित्व डालता है। 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 का दूसरा भाग एक निर्माता द्वारा उल्लंघन के परिणामों से संबंधित है यदि यह पिछले बारह महीनों के दौरान गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों की एमआरपी को एमआरपी के 10% से अधिक बढ़ाता है।

44. इस न्यायालय के लिए अपीलार्थियों के इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है कि 2013 डीपीसीओ का पैरा 20, समग्र रूप से एक दंडात्मक प्रावधान है। इस तथ्य से यह स्थापित होता है कि 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 का उप पैरा (2) विनिर्माताओं को केवल एमआरपी की 10% वृद्धि से अतिप्रभारित को वापस करने का आदेश देता है, जिसे पैरा 20 के तहत ब्याज सहित अनुमति दी गई है। इसके अलावा, पैरा 20 के उप पैरा (2) में "जुर्माना" शब्द इसी अधिनियम की धारा 7 के तहत उल्लिखित दंड को संदर्भित करता है। 2013 डीपीसीओ को इसी अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्ति के आधार पर पारित किया गया है और इसी अधिनियम के तहत आदेशों के उल्लंघन के लिए जुर्माना इसी अधिनियम की धारा 7 के तहत निर्धारित है, न कि 2013 डीपीसीओ के भीतर। जुर्माना केवल मूल कानून के तहत निर्धारित है और इसके तहत किसी आदेश का हिस्सा नहीं हो सकता है। इस प्रकार, 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 के तहत "जुर्माना" शब्द इसी अधिनियम के तहत प्रदान

किए गए प्रावधान से परे कोई अतिरिक्त जुर्माना नहीं बनाता है, जो 2013 डीपीसीओ का मूल कानून है। इसलिए, 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 को दंडात्मक प्रावधान नहीं माना जा सकता है।

45. यह स्थापित करने के बाद कि 2013 डीपीसीओ का पैरा 20 दंडात्मक प्रकृति का नहीं है, इस न्यायालय के समक्ष जो सवाल उठता है वह यह है कि जब कोई निर्माता एक वर्ष में गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों की एमआरपी को 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ाता है तो इसके क्या परिणाम होते हैं।

46. इस मोड़ पर, ऊपर पुनः प्रस्तुत किए गए चार्ट का उल्लेख करना उचित है जो अपीलार्थियों द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दायर लिखित प्रस्तुतियों का एक हिस्सा है। पहला चार्ट उस आदर्श स्थिति का वर्णन करता है जहां एक निर्माता बारह महीनों के बाद गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों के एमआरपी में केवल 10 प्रतिशत की वृद्धि करता है। इसलिए, यदि ऐसे विनिर्मिति की एमआरपी 01.02.2015 को 100 रुपये तय की गई है, तो 01.02.2016 को, विनिर्माता ऐसे विनिर्मितियों की एमआरपी को बढ़ाकर 110 रुपये करने के हकदार है और 01.02.2017 को, यह एमआरपी को 110 रुपये के 10% तक बढ़ाने का हकदार है, यानी, 121 रुपये और इसी तरह।

47. दूसरे चार्ट में, निर्माता 01.02.2015 में गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों की एमआरपी को 100 रुपये से बढ़ाकर 110 रुपये करने के बजाय, एमआरपी को 120 रुपये तक बढ़ाता है और अगले 5 वर्षों के लिए यानी 01.02.2020 तक उसी एमआरपी को बनाए रखता है। सवाल यह है कि 01.02.2020 को जब

अधिकारियों को पता चला कि 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 का उल्लंघन हुआ है, तो गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों की एमआरपी क्या है जिसे निर्माता 01.02.2020 के बाद रखने का हकदार है और निर्माता को सरकार को कितना वापस करना चाहिए। अपीलार्थियों का तर्क यह है कि 01.02.2020 को जब विसंगति का पता चलता है, तो निर्माता को एमआरपी को वापस 110 रुपये पर लाना होगा और उसे केवल 01.02.2021 से एमआरपी को 10% तक बढ़ाने की अनुमति है, जो कि 110 रुपये से अधिक है।

48. इसके विपरीत, यहां प्रत्यर्थागण का तर्क है कि 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 को उचित रूप से पढ़ने से पता चलता है कि एक विनिर्माता ऐसे गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों की एमआरपी को 01.02.2015 को रु. 110/- रुपये, 01.02.2016 को 121/- रुपये 01.02.2017 को रु. 133/- रुपये तक वृद्धि कर सकता है। प्रत्यर्थागण का तर्क है कि यदि विनिर्माता 01.02.2015 को एमआरपी बढ़ाकर 120 रुपये कर देता है, जबकि वह इसे बढ़ाकर रु.110/- रुपये करने का हकदार था, तो विनिर्माता केवल रु.120/- और रु. 110/- रुपये के बीच के अंतर यानी 01.02.2015 से 31.01.2016 तक शुरू होने वाले वर्ष के लिए 10/- रुपये वापस करने के लिए उत्तरदायी है, और उल्लंघन पाए जाने पर विनिर्माता को 01.02.2020 को इसके विनिर्मिति की एमआरपी 110/- रुपये तय करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। उनका तर्क है कि 01.02.2020 को, निर्माता को विनिर्मिति की एमआरपी 177.16/- रुपये रखने

की अनुमति दी जानी चाहिए, यानी 161.05 रुपये की 10% वृद्धि कि अनुमति ।

49. जैसा कि पहले कहा गया है, 2013 डीपीसीओ का पैरा 20 गैर-अनुसूचित विनिर्मिति के एमआरपी की निगरानी से संबंधित है, जो विनिर्माता को पिछले बारह महीनों के दौरान ऐसे विनिर्मिति के एमआरपी को 10% तक बढ़ाने की अनुमति देता है। पैरा 20 में यह भी कहा गया है कि यदि एमआरपी में वृद्धि एमआरपी के 10% से अधिक है, तो अगले बारह महीनों के लिए, ऐसे विनिर्मिति की एमआरपी को एमआरपी के 10% तक कम कर दिया जाएगा जैसा की यह पिछले बारह महीनों में मौजूद था। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझाने के लिए, यदि 01.02.2014 को एक गैर-अनुसूचित विनिर्मिति की एमआरपी 100/- रुपये है, तो निर्माता को 01.02.2015 को 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 के अनुसार ऐसे विनिर्मिति की एमआरपी 110/- रुपये तक बढ़ाने की अनुमति है। हालाँकि, यदि निर्माता 01.02.2015 को ऐसे किसी विनिर्मिति की एमआरपी को 110 रुपये से अधिक, जैसे कि 120/- रुपये तक बढ़ाता है, तो उसे अगले बारह महीनों के लिए ऐसे विनिर्मिति की एमआरपी को घटाकर 110/- रुपये करने की आवश्यकता होती है।

50. इस बिंदु पर 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 में इस्तेमाल किए गए वाक्यांशों "पिछले बारह महीनों" और "अगले बारह महीनों" की व्याख्या करना महत्वपूर्ण हो जाता है। निर्माण के शाब्दिक नियम के सिद्धांत को लागू करते हुए देखें: जे.पी. बंसल बनाम राजस्थान राज्य, (2003) 5 एससीसी 134, नाथी देवी

बनाम राधा देवी गुप्ता, (2005) 2 एससीसी 271; और विजय नारायण थट्टे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2009) 9 एससी सी 92] वाक्यांश की व्याख्या बारह महीने की समय अवधि के अर्थ में की जानी चाहिए, उस तारीख से तुरंत पहले जब गैर-अनुसूचित विनिर्मिति की एमआरपी बढ़ाई गई थी। इसी प्रकार, वाक्यांश "अगले बारह महीने" का अर्थ उस तारीख के तुरंत बाद बारह महीने की समयावधि से लगाया जाना चाहिए जब गैर-अनुसूचित विनिर्मिति की एमआरपी बढ़ाई गई थी। इसलिए, अपीलकर्ताओं द्वारा सुझाए गए शब्दों "पूर्ववर्ती" और "अगले" की व्याख्या वैधानिक व्याख्या के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ होगी और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 को इस तरह पढ़ा जाना चाहिए कि विनिर्माता द्वारा उल्लंघन/अपराध की तारीख का मतलब वह तारीख है जिससे ऐसे विनिर्माता ने एक वर्ष में गैर अनुसूचित विनिर्मिति की एमआरपी में 10% से अधिक की वृद्धि की है।

51. 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 के उप पैरा (2) में कहा गया है कि यदि कोई निर्माता उपभोक्ताओं से अधिक शुल्क लेता है तो उक्त निर्माता जुर्माने के अलावा एमआरपी में वृद्धि की तारीख से ब्याज के साथ अतिप्रभारित राशि जमा करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसका मतलब यह होगा कि अतिप्रभारित राशि जमा करने के लिए निर्माता की देनदारी उस तारीख से उत्पन्न होगी जब एमआरपी को 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 के उप पैरा (1) के तहत अनुमेय 10% एमआरपी वृद्धि से अधिक बढ़ाया गया है। अतिप्रभारित जमा करने का

निर्माता का कर्तव्य मांग सूचना जारी होने पर निर्भर नहीं है। आगे यह स्थापित करता है कि निर्माता द्वारा उल्लंघन/व्यतिक्रम की तारीख का मतलब उस तारीख है जब से निर्माता ने एक वर्ष में गैर-अनुसूचित विनिर्मिति की एमआरपी में 10% से अधिक की वृद्धि की है।

52. 2013 डीपीसीओ के पैराग्राफ 23 ("पैरा 23") में कहा गया है कि सरकार नोटिस के जरिए उक्त आदेश के तहत सरकार द्वारा निर्माताओं, आयातक या वितरक या जैसा भी मामला हो, को निर्धारित या अधिसूचित कीमतों से अतिप्रभारित वसूलने के कारण अर्जित राशि जमा करने के लिए कहेगी। 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 (2) और पैरा 23 का एक संयुक्त पठन आगे दर्शाता है कि 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 के तहत उल्लंघन/व्यतिक्रम की तारीख को उस तारीख के लिए पढ़ा जाना चाहिए जिससे निर्माता ने एक वर्ष में गैर-अनुसूचित विनिर्मिति के एमआरपी में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की है, और इसे उस तारीख के लिए नहीं पढ़ा जाना चाहिए जिससे ऐसे निर्माता को मांग सूचना जारी की जाती है।

53. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, जब कोई निर्माता किसी गैर-अनुसूचित विनिर्मिति की एमआरपी प्रति वर्ष 10% से अधिक बढ़ाता है तो परिणाम इस प्रकार होते हैं:

क. निर्माता पर ईसी अधिनियम की धारा 7 के तहत निर्धारित जुर्माना लगाया जा सकता है।

ख. निर्माता अगले बारह महीनों के लिए ऐसे गैर-अनुसूचित विनिर्मिति की एमआरपी को अनुज्ञेय एमआरपी की 10% वृद्धि के स्तर तक कम करने के लिए उत्तरदायी है। अगले बारह महीनों के लिए एमआरपी कम करने का निर्माता का दायित्व उस तारीख से उत्पन्न होता है जिस दिन एमआरपी 10% से अधिक बढ़ाई गई थी। इसलिए, यदि किसी गैर-अनुसूचित विनिर्मिति की एमआरपी 01.02.2014 को 100/- रुपये है, तो 01.02.2015 को एमआरपी को 110/- रुपये तक बढ़ाने का हकदार है। हालाँकि, यदि निर्माता 01.02.2015 को एमआरपी बढ़ाकर रु.120/- कर देता है, तो 01.02.2015 से, निर्माता का दायित्व है कि वह अगले बारह महीनों के लिए, यानी 31.01.2016 तक एमआरपी घटाकर रु.110/- कर दे।

ग. विनिर्माता सरकार के पास ब्याज सहित अतिप्रभारित राशि जमा करने के लिए उत्तरदायी है। वह तारीख, जिस तारीख से किसी निर्माता की अतिप्रभारित राशि जमा करने की देनदारी होती है, वह तारीख होती है, जब से गैर-अनुसूचित व्यतिक्रम की कीमत अनुमेय 10% वृद्धि से अधिक बढ़ गई है। अधिक वसूली गई राशि की गणना "एमआरपी में वास्तविक वृद्धि" और "एमआरपी में अनुज्ञेय वृद्धि" के बीच के अंतर के रूप में की जाएगी। इसलिए, यदि एमआरपी में अनुज्ञेय वृद्धि 110/- रुपये है, लेकिन एमआरपी वास्तव में 120/- रुपये तक बढ़ गई है, तो अधिभारित राशि 120/ और रुपये 110/- का अंतर आती है, यानी, 10/- रुपये होगी ।

54. उक्त प्रावधान का उल्लंघन/व्यतिक्रम कब होता है और इस तरह के व्यतिक्रम के परिणाम क्या हैं, इसके संदर्भ में 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 की व्याख्या से निपटने के बाद, एकमात्र प्रश्न जो इस न्यायालय के ध्यान की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या कोई विनिर्माता है किसी गैर-अनुसूचित विनिर्मिति के एमआरपी को पूर्णांकन करने का हकदार है और यदि पूर्णांकन की अनुमति है, तो इस तरह के पूर्णांकन को किस तरीके से किया जा सकता है।

55. इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों ने कहा है कि पूर्णांकन की अवधारणा वास्तव में औषधियों की कीमतों पर लागू नहीं होती है क्योंकि एलएमपीसी नियमों के नियम 26 में 2013 डीपीसीओ के तहत अनुसूचित और गैर-अनुसूचित विनिर्मिति के लिए इन नियमों की प्रयोज्यता शामिल नहीं है। उनका मामला यह है कि एनपीपीए की 12.04.2016 की बैठक के कार्यवृत्त के पैरा 5.2 पर गैर-अनुसूचित विनिर्मिति पर पूर्णांकन के सिद्धांत को लागू करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है, और यदि यह लागू भी है, पूर्णांक के लाभ की अनुमति केवल दो दशमलव अंकों तक है। उनका तर्क है कि ऑब्जर्ज बायोटेक (उपरोक्त) में निर्णय पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रखी गई निर्भरता गलत है क्योंकि इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा इस पर रोक लगा दी गई है।

56. इसके विपरीत, प्रत्यर्थागण ने गैर-अनुसूचित विनिर्मिति पर पूर्णांकन के सिद्धांत को लागू करने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दी गई

व्याख्या और तर्क का समर्थन करते हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने पूर्णांकन के मुद्दे से निपटते समय यह पाया कि इसका कोई औचित्य नहीं है कि पूर्णांकन का लाभ केवल अनुसूचित विनिर्मिति तक ही क्यों बढ़ाया जा सकता है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने एनपीपीए की दिनांक 12.04.2016 की बैठक के कार्यवृत्त के पैरा 5.2 पर भरोसा करते हुए कहा कि उसमें इस्तेमाल किए गए शब्द "विनिर्मिति" को अनुसूचित और गैर-अनुसूचित विनिर्मिति दोनों के अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए। विद्वान एकल न्यायाधीश ने किसी औषधि की एमआरपी को दशमलव बिंदुओं में तय करने में उपभोक्ताओं और आपूर्तिकर्ताओं को आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखा और इस प्रकार माना कि पूर्णांकन का सिद्धांत गैर-अनुसूचित विनिर्मिति पर भी लागू होता है।

57. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि की गई टिप्पणियाँ ऑब्जर्ज बायोटेक (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय से प्रभावित हुए बिना हैं क्योंकि उक्त निर्णय एलपीए संख्या 310/2020 में चुनौती का विषय है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया तर्क और विश्लेषण ऑब्जर्ज बायोटेक (उपरोक्त) के फैसले से स्वतंत्र है और यह कहना गलत होगा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने उसी पर भरोसा किया है।

58. इस समय एनपीपीए की बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 12.04.2016 के पैरा 5 का उल्लेख करना उचित होगा, जो निम्नानुसार है:

“कार्यसूची मद सं. 5 (ii):-पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के डब्ल्यूपीआई के आधार पर दो दशमलव अंकों तक विनिर्मिति के लिए अधिकतम कीमत निर्धारित करने के कारण अधिक शुल्क लेना।

5.2 कार्यसूची पर चर्चा की गई। यह निर्णय लिया गया कि एनपीपीए उन अतिप्रभारित मामलों को आगे नहीं बढ़ाएगा जो सामान्य गणितीय अभ्यास के अनुसार दशमलव अंकों को पूर्णांकित करने के कारण विशुद्ध रूप से गणितीय गणना से उत्पन्न हुए थे और कंपनी की ओर से कोई अन्य दुर्भावनापूर्ण इरादा स्पष्ट नहीं था।”

(जोर दिया गया)

59. उपरोक्त को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि एनपीपीए ने उन अधिक शुल्क लेने वाले मामलों को आगे नहीं बढ़ाने का एक सचेत निर्णय लिया है जो सामान्य गणितीय अभ्यास के अनुसार दशमलव अंकों को पूरा करने के कारण विशुद्ध रूप से गणितीय गणना से उत्पन्न होते हैं और कंपनी की ओर से कोई अन्य असद्भावी इरादा स्पष्ट नहीं था। यह भी स्पष्ट है कि उक्त बैठक में एनपीपीए मुख्य रूप से निर्धारित विनिर्मिति के साथ काम कर रहा था, जैसा कि वही संदर्भित करता है “अधिकतम मूल्य “और” थोक मूल्य सूचकांक” (‘डब्ल्यूपीआई’), जो निर्धारित विनिर्मिति की कीमत की गणना के लिए प्रासंगिक कारक हैं। इसके अलावा, कार्यसूची मद सं. 5(ii) स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि पूर्णांकित का लाभ, यहां तक कि निर्धारित विनिर्मिति के लिए भी, केवल दो दशमलव अंकों तक फैला हुआ है।

60. जबकि अपीलार्थी यह कहने में सही हैं कि एनपीपीए की बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 12.04.2016 का पैरा 5 केवल अनुसूचित विनिर्मिति से संबंधित है, इस न्यायालय को इस तर्क को प्रतिग्रहण करना मुश्किल लगता है कि पूर्णांकन का लाभ गैर-अनुसूचित विनिर्मिति को नहीं दिया जा सकता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, केंद्र सरकार की ओर से गैर-अनुसूचित विनिर्मिति को मूल्य नियंत्रण की कठोरता से बाहर करने और इसके बजाय अधिक उदार मूल्य निगरानी प्रणाली अपनाने का एक सचेत निर्णय लिया गया है। इस न्यायालय को कोई तर्क या औचित्य खोजना मुश्किल लगता है कि पूर्णांकन का लाभ केवल अनुसूचित विनिर्मिति तक ही सीमित क्यों हो सकता है, जो बहुत सख्त मूल्य नियंत्रण व्यवस्था द्वारा नियंत्रित होते हैं। 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 के तहत परिकल्पित मूल्य निगरानी प्रणाली अधिक उदार है, और गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों को भी पूर्णांकन का लाभ नहीं देने का कोई उचित आधार नहीं है। इस न्यायालय के सुविचारित राय में, पूर्णांकन के सिद्धांत की प्रयोज्यता को केवल अनुसूचित विनिर्मिति तक सीमित करना अनुचित और मनमाना होगा। इस हद तक, इस न्यायालय को विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले में कोई कमजोरी नहीं मिलती है।

61. हालाँकि यह न्यायालय अपीलार्थियों के इस तर्क से सहमत है कि पूर्णांकन के लाभ की अनुमति केवल दो दशमलव अंकों तक है। एनपीपीए के दिनांक 12.04.2016 की बैठक के कार्यवृत्त का पैरा 5 स्पष्ट रूप से सामान्य गणितीय अभ्यास के अनुसार अनुसूचित विनिर्मितियों के लिए उपलब्ध पूर्णांकन के लाभ

को दो दशमलव स्थानों तक सीमित करता है। तदनुसार, गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों के लिए भी, पूर्णांकन सामान्य गणितीय अभ्यास के अनुसार दो दशमलव स्थानों तक सीमित होना चाहिए।

62. यह ध्यान रखना उचित है कि एलएमपीसी नियमों का नियम 26 स्पष्ट रूप से अनुसूचित और गैर-अनुसूचित दोनों विनिर्मितियों को इसके दायरे से बाहर रखता है, और इसलिए पूर्णांकन के लिए इसमें प्रदान की गई व्यवस्था अनुसूचित या गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों पर लागू नहीं होगी। यह एनपीपीए की दिनांक 12.04.2016 की बैठक के कार्यवृत्त के पैरा 5.2 में प्रयुक्त वाक्यांश "सामान्य गणितीय अभ्यास" से भी स्पष्ट है। यह प्रदर्शित करने के लिए कि गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों की कीमतों को कैसे पूर्णांकित किया जा सकता है, निम्नलिखित उदाहरणों का संदर्भ लिया जा सकता है:

क्र.सं.	वास्तविक आंकड़ा	पूर्णांकित आंकड़ा
1.	रु. 123.45/-	रु. 123.45/-
2.	रु. 123.455/-	रु. 123.46/-
3.	रु. 123.456/-	रु. 123.46/-
4.	रु. 123.991/-	रु. 123.99/-
5.	रु. 123.999/-	रु. 124.00/-
6.	रु. 123.001/-	रु. 123.00/-
7.	रु. 123.111/-	रु. 123.11/-

63. इसलिए, जबकि पूर्णांकित का सिद्धांत गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों के साथ-साथ अनुसूचित विनिर्मितियों पर भी लागू होता है, पूर्णांकित का लाभ केवल दो दशमलव स्थानों तक बढ़ाया जाता है, और केवल तब जब कंपनी की ओर से कोई अन्य दुर्भावनापूर्ण इरादा स्पष्ट नहीं है। यह एनपीपीए द्वारा दिनांक 12.04.2016 की बैठक के कार्यवृत्त के पैरा 5.2 में अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुरूप है।

64. पैरा 20 की उपरोक्त व्याख्या में और अधिक स्पष्टता लाने के लिए, 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 की व्याख्या विभिन्न उदाहरणों में कैसे की जा सकती है, इस पर निम्नलिखित उदाहरणों का उल्लेख किया जा सकता है। निम्नलिखित उदाहरणों के लिए, उसमें बताए गए परिणाम इसी अधिनियम की धारा 7 के तहत निर्धारित दंड के अतिरिक्त होंगे। इसके अलावा, निम्नलिखित उदाहरणों में एकरूपता के उद्देश्य से, निर्माता द्वारा 01.02.2014 को निर्मित गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों की एमआरपी 100/- रुपये मानी गई है। इसका अर्थ यह होगा कि 01.02.2015 को, पिछले बारह महीनों के लिए गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों की एमआरपी 100/- रुपये है। इसलिए 01.02.2015 को, निर्माता गैर-अनुसूचित विनिर्मिति की एमआरपी को रु. 110/- तक बढ़ाने का हकदार होगा।

65. उपरोक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए, 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 की व्याख्या को प्रदर्शित करने के लिए काल्पनिक चित्र इस प्रकार हैं:

क. विनिर्माता ने 01.02.2015 को गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों की एमआरपी बढ़ाकर 110/- रुपये कर दी। इसके बाद, 01.02.2016 को, विनिर्माता ने एमआरपी को बढ़ाकर 121/- रुपये कर दिया। ऐसे परिदृश्य में, कोई दंडात्मक परिणाम नहीं होगा क्योंकि निर्माता ने 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 के अनुसार एमआरपी में 10% की वृद्धि की है।

ख. निर्माता 01.02.2015 को गैर-अनुसूचित विनिर्मिति की एमआरपी बढ़ाकर 110/- रुपये कर देता है । इसके बाद वह 01.02.2016 को एमआरपी को 10% बढ़ाकर 121/- रुपये कर देता है, फिर 01.02.2017 को इसे बढ़ाकर 133.1/- रुपये कर देता है। इस वार्षिक वृद्धि को 10% तक जारी रखते हुए, निर्माता 01.02.2018 को एमआरपी बढ़ाकर 146.41/- रुपये और फिर 01.02.2019 को 161.05/- रुपये कर देता है। 01.02.2020 को गैर-अनुसूचित विनिर्मिति की एमआरपी को और बढ़ाकर रु. 177.16/- वृद्धि कर देता है ऐसे परिदृश्य में, कोई दंडात्मक परिणाम नहीं होगा। ऐसा इसलिए है, क्योंकि एमआरपी में 161.05/- रुपये से 10% की बढ़ोतरी के बावजूद यह रु. 177.155/- हो जाती है सामान्य गणितीय अभ्यास के अनुसार निर्माता उक्त आंकड़े को दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करने का हकदार है।

ग. आइए उपरोक्त उदाहरण को आगे ले जाएं, जहां प्रति वर्ष एमआरपी में 10% की बढ़ोतरी होती है। ऐसे मामले में प्रगति 01.02.2015 को

रु.110/- , 01.02.2016 को रु 121/-; 01.02.2017 को रु.133.1/-; 01.02.2018 को रु.146.41/-; 01.02.2019 को रु.161.05/-; और 01.02.2020 को 177.16/- रु. हो जाएगी; 01.02.2021 को, निर्माता ने एमआरपी बढ़ाकर 195/- रुपये कर दी। ऐसे मामले में, विनिर्माता 01.02.2021 से ही एमआरपी को वापस 194.88/- रुपये करने के लिए उत्तरदायी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रु.177.16/- की 10% वृद्धि रु.194.876/- होती है, जिसे निकटतम दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करने पर रु.194.88/- आती है। इसके अलावा, 01.02.2021 से, निर्माता सरकार को अतिप्रभारित राशि, यानी 195 रुपये और 194.88 रुपये के बीच का अंतर, यानी 0.12/- रुपये, ब्याज सहित जमा करने के लिए उत्तरदायी है।

घ. निर्माता ने 01.02.2015 को गैर-अनुसूचित विनिर्मिति की एमआरपी बढ़ाकर 121/- रुपये कर दी। ऐसे मामले में, विनिर्माता 01.02.2015 से ही एमआरपी को घटाकर 110/- रुपये करने के लिए उत्तरदायी है। तदनुसार, 15.02.2015 को, विनिर्माता ने एमआरपी को घटाकर 110/- रुपये कर दिया। ऐसे मामले में, निर्माता को 31.01.2016 तक, यानी उल्लंघन की तारीख से अगले 12 महीनों तक एमआरपी 110/- रुपये रखनी होगी। विनिर्माता ब्याज सहित 01.02.2015 से 15.02.2015 के बीच अधिक ली गई राशि, यानी 11/- रुपये जमा करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

ड. निर्माता ने 01.02.2015 को गैर-अनुसूचित विनिर्मिति की एमआरपी 100/- रुपये बरकरार रखी है। इसके बाद 01.05.2015 को, निर्माता ने गैर-अनुसूचित विनिर्मिति की एमआरपी बढ़ाकर 105/- रुपये कर दी। यह स्वीकार्य है क्योंकि पिछले बारह महीनों के दौरान एमआरपी वृद्धि एमआरपी के 10% से कम है। यदि निर्माता 01.02.2016 को फिर से गैर-अनुसूचित विनिर्मिति की एमआरपी 110/- रुपये तक बढ़ा देता है, तो इसकी अनुमति नहीं होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि विनिर्माता को अगले बारह महीनों के लिए एमआरपी में वृद्धि को संरक्षित करना आवश्यक है। इस मामले में विनिर्माता 01.02.2016 से एमआरपी को 105/- रुपये पर वापस लाने के लिए बाध्य होगा और 01.02.2016 से ब्याज के साथ अतिप्रभारित राशि जमा करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

च. विनिर्माता ने 01.02.2015 को गैर-अनुसूचित विनिर्मिति की एमआरपी 100/- रुपये बरकरार रखी है। इसके बाद 01.05.2015 को, निर्माता ने गैर-अनुसूचित विनिर्मिति की एमआरपी बढ़ाकर 105/- रुपये कर दी। यह स्वीकार्य है क्योंकि पिछले बारह महीनों के दौरान एमआरपी वृद्धि एमआरपी के 10% से कम है। यदि निर्माता 01.02.2016 को फिर से गैर-अनुसूचित विनिर्मिति की एमआरपी 110/- रुपये तक बढ़ा देता है, तो इसकी अनुमति नहीं होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि विनिर्माता को अगले

बारह महीनों के लिए एमआरपी में वृद्धि को संरक्षित करना आवश्यक है। इस मामले में विनिर्माता 01.02.2016 से एमआरपी को 105/- रुपये पर वापस लाने के लिए बाध्य होगा और 01.02.2016 से ब्याज के साथ अतिप्रभारित राशि जमा करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

छ. विनिर्माता ने 01.02.2015 को गैर-अनुसूचित विनिर्मिति की एमआरपी बढ़ाकर रु.105/- कर दी। ऐसे मामले में, 01.02.2016 को, विनिर्माता एमआरपी को 115.5/- रुपये तक बढ़ाने का हकदार होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि 01.02.2016 से पिछले बारह महीनों में एमआरपी रु. 105/- और 105/- की 10% वृद्धि 115.5/- होगी। ऐसे मामले में निर्माता 121/- रुपये शुल्क लेने का हकदार नहीं होगा, यानी, 110/- रुपये की 10% वृद्धि। ऐसा इसलिए है क्योंकि 01.02.2016 को अनुज्ञेय एमआरपी वृद्धि पिछले बारह महीनों के लिए वास्तविक एमआरपी के 10% (105/- रुपये) पर आधारित है, न कि पिछले बारह महीनों के लिए अनुज्ञेय एमआरपी के 10% (110/- रुपये) पर आधारित है। -). उपरोक्त उदाहरण में, यदि विनिर्माता 01.02.2016 को गैर-अनुसूचित विनिर्मिति की एमआरपी बढ़ाकर रु.121/- कर देता है, तो एमआरपी वृद्धि की तारीख यानी, 01.02.2016 से, विनिर्माता एमआरपी को घटाकर रु.115.5 करने के लिए उत्तरदायी है। -/ यानि 31.01.2017 तक अनुमन्य 10% वृद्धि। 01.02.2016 से, निर्माता अतिप्रभारित राशि, यानी 121/- रुपये और

115.5/- रुपये के बीच का अंतर, यानी 5.5/- रुपये, ब्याज सहित वापस करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

ज. 01.02.2015 को, विनिर्माता ने एमआरपी बढ़ाकर रु.121/- कर दी। तब विनिर्माता 01.02.2015 से ही एमआरपी को घटाकर 110/- रुपये करने के लिए उत्तरदायी है। हालाँकि, विनिर्माता ऐसा नहीं करता है, और 31.01.2017 तक एमआरपी 121/- रुपये पर बनाए रखता है। ऐसे परिदृश्य में, निर्माता 01.02.2015 और 31.01.2016 के बीच अधिक ली गई राशि, यानी 11/- रुपये, ब्याज सहित जमा करने के लिए उत्तरदायी है। हालाँकि, विनिर्माता 01.02.2016 और 31.01.2017 की अवधि के लिए कोई भी राशि जमा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसा इसलिए है, क्योंकि विनिर्माता 01.02.2015 और 31.01.2016 के बीच की अवधि के लिए एमआरपी केवल 110/- रुपये रखने के लिए उत्तरदायी है। विनिर्माता 01.02.2016 से एमआरपी को 121/- रुपये तक बढ़ाने का हकदार है

झ. विनिर्माता ने 01.02.2015 को एमआरपी बढ़ाकर 135/- रुपये कर दी। विनिर्माता 01.02.2015 से ही एमआरपी को घटाकर 110/- रुपये करने के लिए उत्तरदायी है। हालाँकि विनिर्माता 31.01.2018 तक ऐसा नहीं करता है। ऐसे मामले में, अधिक चार्ज की गई राशि जमा करने के लिए विनिर्माता का दायित्व होगा: (i) 01.02.2015 से 31.01.2016 के बीच की अवधि के लिए रु.25/-; (ii) 01.02.2016 से 31.01.2017 के बीच की अवधि के लिए रु.14/-; और (iii) 01.02.2017 से 31.01.2018

के बीच की अवधि के लिए रु.1.9/-। 01.02.2018 को, निर्माता विनिर्मिति की एमआरपी 135/- रुपये रखने का हकदार होगा और वह 01.02.2019 को एमआरपी 148.5/- रुपये तक बढ़ाने का हकदार होगा, यानी 135 रुपये से 10% की बढ़ोतरी /-, जो पिछले बारह महीनों के लिए प्रचलित एमआरपी होगी।

ज. 01.02.2015 को, विनिर्माता ने एमआरपी बढ़ाकर रु.121/- कर दिया । इसके बाद 01.02.2016 को, विनिर्माता ने एमआरपी बढ़ाकर 133.1/- रुपये कर दिया । ऐसे मामले में, 01.02.2015 से, विनिर्माता 01.02.2015 से 31.01.2016 तक एमआरपी को घटाकर 110/- रुपये करने के लिए उत्तरदायी है, और फिर 01.02.2016 से 31.01.2017 तक एमआरपी को घटाकर 121/- रुपये करने के लिए उत्तरदायी है। तदनुसार, अतिप्रभारित राशि जमा करने के लिए निर्माता का दायित्व होगा: (i) 01.02.2015 और 31.01.2016 के बीच की अवधि के लिए रु.11/-; और (ii) 01.02.2016 और 31.01.2017 के बीच की अवधि के लिए रु. 12.1/-। इस मामले में, भले ही निर्माता ने 01.02.2016 को एमआरपी 10% बढ़ाकर रु.121/- से रु.133.1/- कर दी। वह ऐसा करने का हकदार नहीं होगा क्योंकि पिछली वृद्धि स्वयं 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 का उल्लंघन थी। ऐसी स्थिति में, जहां पिछले बारह महीनों के लिए एमआरपी स्वयं 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 का उल्लंघन है, विनिर्माता केवल उस एमआरपी के आधार पर एमआरपी बढ़ाने का हकदार होगा जो विनिर्माता पिछले बारह महीनों के

लिए रखने का हकदार था। इसलिए, वर्तमान मामले में, चूंकि निर्माता केवल 01.02.2015 को एमआरपी को 110/- रुपये तक बढ़ाने का हकदार था, इसलिए उसे 01.02.2016 को एमआरपी को 133.1/- रुपये तक बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, बल्कि केवल 121 रुपये तक बढ़ाने की अनुमति दी जा सकती थी। निर्माता 01.02.2017 को एमआरपी को केवल 133.1/- रुपये तक बढ़ाने का हकदार होगा।

66. संक्षेप में कहें तो:

क. 2013 डीपीसीओ, 1995 डीपीसीओ के विपरीत, केवल औषधि विनिर्मितियों पर लागू होता है, प्रपुंज औषधि पर नहीं। इसके अलावा, 2013 डीपीसीओ अनुसूचित औषधि विनिर्मितियों के लिए एक मूल्य नियंत्रण तंत्र और गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों के लिए एक मूल्य निगरानी तंत्र की परिकल्पना करता है। 2013 डीपीसीओ के तहत सरकार के पास केवल अनुसूचित विनिर्मितियों की कीमतें तय करने और संशोधित करने की शक्ति है और गैर अनुसूचित विनिर्मितियों के संबंध में, सरकार केवल गैर अनुसूचित विनिर्मितियों के एमआरपी में बदलाव की निगरानी कर सकती है। इसलिए, 2013 डीपीसीओ के तहत, गैर-अनुसूचित विनिर्मितिया मूल्य नियंत्रण व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनते हैं, बल्कि एनपीपीपी 2012 के तहत परिकल्पित मूल्य निगरानी तंत्र का एक हिस्सा हैं।

ख. 2013 डीपीसीओ का पैरा 20 दो अलग और पहचान योग्य भागों में विभाजित है। पहले भाग में प्रावधान है कि एक गैर-अनुसूचित विनिर्मिति

का विनिर्माता पिछले बारह महीनों के दौरान अपनी एमआरपी को एमआरपी के 10% तक बढ़ा सकता है, अगले बारह महीनों के लिए उक्त एमआरपी को संरक्षित कर सकता है और सरकार पर ऐसे गैर-अनुसूचित विनिर्मिति की एमआरपी में वृद्धि की निगरानी करने का दायित्व डालता है। 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 का दूसरा भाग एक निर्माता द्वारा किए गए उल्लंघन के परिणामों से संबंधित है, यदि यह पिछले बारह महीनों के दौरान गैर-अनुसूचित विनिर्मिति की एमआरपी को एमआरपी के 10% से अधिक बढ़ा देता है।

ग.2013 डीपीसीओ के तहत गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों के लिए स्थापित मूल्य निगरानी तंत्र ; लोक/उपभोक्ता हित को सर्वोपरि मानता है और उचित मूल्य पर औषधि के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए 2013 डीपीसीओ के उद्देश्य के अनुरूप है।

घ.2013 डीपीसीओ के पैरा 20 को समग्र रूप से दंडात्मक प्रावधान नहीं कहा जा सकता है। 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 के उप पैरा (2) में प्रयुक्त शब्द "जुर्माना" इसी अधिनियम की धारा 7, यानी 2013 डीपीसीओ के मूल कानून के तहत प्रदान किए गए दंड को संदर्भित करता है।

ड.2013 डीपीसीओ के पैरा 20 में वाक्यांश "बारह महीने से पहले" का मतलब उस तारीख से ठीक पहले बारह महीने की समय अवधि है जब गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों की एमआरपी बढ़ाई गई थी। इसी तरह, 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 में वाक्यांश "अगले बारह महीने" का मतलब उस

तारीख के तुरंत बाद बारह महीने की समय अवधि है जब गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों की कीमत में वृद्धि हुई थी। परिणामस्वरूप , 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 के उल्लंघन की तारीख का मतलब वह तारीख होना चाहिए, जब से एक विनिर्माता ने बारह महीने की अवधि में गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों की एमआरपी में 10% से अधिक की वृद्धि की है।

च.2013 डीपीसीओ के पैरा 20 और पैरा 23 को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलता है कि 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 के उल्लंघन की तारीख का मतलब उस तारीख से नहीं हो सकता जिस दिन विनिर्माता को मांग नोटिस जारी किया जाता है। लेकिन इसे उस तारीख के रूप में पढ़ा जाना चाहिए जिस दिन निर्माता ने बारह महीने की अवधि में गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों की एमआरपी में 10% से अधिक की वृद्धि की है।

छ. 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 के उल्लंघन पर होने वाले परिणाम इस प्रकार हैं:

- i. निर्माता इसी अधिनियम की धारा 7 के तहत निर्धारित दंड के अधीन हो सकता है।
- ii. निर्माता अगले बारह महीनों के लिए ऐसे गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों की एमआरपी को अनुमेय एमआरपी की 10% वृद्धि के स्तर तक कम करने के लिए उत्तरदायी है। अगले बारह महीनों के लिए एमआरपी कम करने का निर्माता का दायित्व उस तारीख

से उत्पन्न होता है जिस दिन एमआरपी 10% से अधिक वृद्धि कि गई थी।

///. विनिर्माता सरकार के पास ब्याज सहित अतिप्रभारित राशि जमा करने के लिए उत्तरदायी है। वह तारीख, जिस तारीख से किसी विनिर्माता की अतिप्रभारित राशि जमा करने की देनदारी होती है, वह तारीख होती है, जब से गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों की कीमत 10% अनुज्ञेय वृद्धि से अधिक वृद्धि कर दी गई हो। अधिक वसूली गई राशि की गणना "एमआरपी में वास्तविक वृद्धि" और "एमआरपी में अनुज्ञेय वृद्धि" के बीच के अंतर के रूप में की जाएगी।

ज. एनपीपीए की दिनांक 12.04.2016 की बैठक के कार्यवृत्त के पैरा 5.2 में दिए गए पूर्णांकन का लाभ गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशनों पर भी बढ़ाया जाना चाहिए। इसमें दिए गए पूर्णांकन के लाभ को केवल अनुसूचित फॉर्मूलेशन तक सीमित करना अनुचित और मनमाना है।

झ. सामान्य गणितीय अभ्यास के अनुसार पूर्णांकन का लाभ केवल दो दशमलव बिंदुओं तक ही दिया जाता है और केवल तभी जब कंपनी की ओर से कोई अन्य गलत इरादा स्पष्ट न हो। एलएमपीसी नियमों के तहत दिए गए पूर्णांकन के लिए एलपीए 118/2023 आदि पृष्ठ 48 में से 48 तंत्र 2013 डीपीसीओ के तहत औषधि विनिर्मितियों पर लागू नहीं है।

ज. किसी निर्माता के लिए गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशन की एमआरपी को एक वर्ष में अधिकतम अनुज्ञेय 10% तक बढ़ाना आवश्यक नहीं है।

ट. 2013 डीपीसीओ के पैरा 20 के तहत अनुज्ञेय एमआरपी में 10% वृद्धि की गणना पिछले बारह महीनों में गैर-अनुसूचित विनिर्मितियों की वास्तविक एमआरपी के आधार पर की जानी चाहिए, न कि पिछले बारह महीनों के लिए अनुज्ञेय एमआरपी के आधार पर।

67. इन टिप्पणियों के साथ, लंबित आवेदन (नों), यदि कोई हो, के साथ अपीलों का निपटान किया जाता है।

मु. न्या. सतीश चंद्र शर्मा

न्या. सुब्रमण्यम प्रसाद

नवंबर 08, 2023

अर्श/एस. जाकिर

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।